मेट्रो Rays

आगे रखने का वादा

सांध्य दैनिक

रांची, शुक्रवार, 24 जुलाई 2026

संवत 2083, अषाढ़ शुक्ल 10 मूल्य-3 रुपये

वर्ष-9, अंक 310 , पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

4 ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं स्मार्ट भंडारण भी जरूरी

पंच से पहले ही भारत का पदक पक्का, लवलीना को बाई मिली, बिना लड़े सेमीफाइनल में पहुंचीं 6

जमशेदपुर: डिमना लेक मे डूबने से एमजीएम के दो जूनियर डॉक्टरों की मौत

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जमशेदपुर: शहर के डिमना लेक में डूबने से एमजीएम अस्पताल के दो जूनियर डॉक्टरों की मौत हो गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। मामले में ग्रामीम एसपी ने बताया की रेस्क्यू अभियान के जरिए दोनों डॉक्टर का शव निकाला गया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद अस्पताल में शोक का माहौल है।

दोनों डॉक्टर के शव को लेक से निकाला बाहरः जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज के दो जूनियर डॉक्टर्स समीर और सक्षम सिंह का गुरुवार रात करीब 11 बजे ड्यूटी समाप्त हुई थी। इसके बाद वे अपने एक अन्य साथी यश के साथ डिमना लेक पहुंचे। बताया जा रहा है कि एक युवक का मोबाइल पानी में गिर गया था। मोबाइल निकालने के लिए वह पानी में उतरा। लेकिन कुछ ही देर में उसका संतुलन बिगड़ने लगा।

अपने दोस्त को मुश्किल में देख दूसरा साथी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन वह भी अपना संतुलन खो बैठा। देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में समा गए और लापता हो गए। वहीं उनके साथ मौजूद तीसरा साथी यश इस हादसे में सुरक्षित बच गया।

दोनों के शव को लेक से निकाला बाहरः दोनों की पहचान काशीडीह निवासी 26 वर्षीय समीर और डाल्टनगंड स्थित बिनेका गांव के 22 वर्षीय सक्षम सिंह के रूप में हुई है। तीसरा डॉक्टर तत्काल घटना की जानकारी अस्पताल में दी। जिसके बाद कई गोताखोरों को बुलाकर रेस्क्यू किया गया। लेकिन दोनों डॉक्टर का पता नहीं चला। इधर सुबह से ही रेसक्यू जारी रहा। काफी मशक्कत के बाद दोनों जूनियर डॉक्टर का शव डिमना लेक से बाहर निकाला गया।

इस घटना के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर और शहर के चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मामले में ग्रामीण एसपी शुभम खंडेवाल ने बताया है कि तीनों जूनियर डॉक्टर आधी रात के बाद वहां क्यों गए और घटना कैसे घटी, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

जगन्नाथपुर मंदिर की वित्तीय व्यवस्था पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, स्पेशल व फॉरेंसिक ऑडिट की मांग

मेट्रो रेज

रांचीः रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर की व्यवस्था और वित्तीय लेन-देन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। धुर्वा निवासी अजय कुमार द्वारा दायर इस याचिका में राज्य सरकार, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति, केनरा बैंक सहित अन्य संबंधित पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा जीएसटी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि समिति का बैंक खाता गलत पैन (पेन) नंबर के आधार पर संचालित किया जा रहा है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

केनरा बैंक की भूमिका पर भी उठाए गए सवालः याचिकाकर्ता ने केनरा बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों की अनदेखी की। आरोप है कि बैंक ने जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का खाता मंदिर पुनर्निर्माण समिति के पैन नंबर के आधार पर संचालित होने दिया, जो बैंकिंग नियमों और वित्तीय मानकों के विपरीत है।

याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि मंदिर न्यास समिति के सभी वित्तीय अभिलेख, बुक्स ऑफ अकाउंट, आय-व्यय का विवरण, दान रजिस्टर, दान पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज तत्काल किसी सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में सौंपे जाएं।

स्पेशल और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांगः जनहित याचिका में मंदिर न्यास समिति पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए समिति का स्पेशल ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट कराने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। इसके अलावा मंदिर के वर्तमान प्रबंधन को न्यास समिति से हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।

अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत के निर्देशों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों की जांच किस प्रकार और किस एजेंसी से कराई जाएगी।

मनी लॉन्ड्रिंग : विनोद सिंह और राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज याचिका खारिज

रांचीः प्रवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने बड़गाई स्थित भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह और राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब उन्होंने डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की है। हालांकि, विनोद सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। इससे पहले रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने गुरुवार को इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के ऊपर आरोप गठित कर दिया है जिसके बाद यह केस अब ट्रायल की ओर बढ़ सकता है।

लातेहार में पीएलएफआई के दो नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार

किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की थी योजना

संवाददाता

लातेहारः पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पीएलएफआई के दो नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सली लातेहार जिले के बालूमाथ में किसी हिंसक घटना को अंजाम देने जा रहे थे। इस दौरान गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली संजय सिंह और मोहम्मद शहजाद दोनों लोहरदगा जिले के रहने वाले हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाईः दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के कुछ नक्सली किसी हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए बाइक पर सवार होकर चंदवा से बालूमाथ की ओर जा रहे हैं। सूचना के बाद लातेहार एसपी के निर्देश पर डीएसपी उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई।

पुलिस छापेमारी के दौरान बालूमाथ थाना अंतर्गत मकइयाटांड़ पुलिस पिकेट के पास चंदवा से बालूमाथ की ओर बाइक पर सवार होकर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस को देखकर दोनों भागने का प्रयास करने लगे। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वे लोग पीएलएफआई के उग्रवादी हैं।

पीएलएफआई कमांडर बादल के कहने पर देने वाले थे हिंसक घटना को अंजामः मामले को लेकर डीएसपी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के उग्रवादी बालूमाथ में दहशत फैलाने के मकसद से किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा गोलियां, चोरी का एक बाइक बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि उग्रवादी क्षेत्र में दहशत फैलाकर लेवी वसूलने की योजना बनाकर बालूमाथ और बरियातू की ओर आ रहे थे। लेकिन सही समय पर पुलिस की कार्रवाई से उग्रवादियों की योजना असफल हो गई।

पीएलएफआई उग्रवादियों की गिरफ्तारी में डीएसपी उमेश कुमार सिंह के अलावे बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, बरियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और अभिमन्यु कुमार व अन्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

हजारीबाग के केरेडारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़

राहुल दुबे गिरोह के एक अपराधी को लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार

मेट्रो रेज

हजारीबागः शुक्रवार देर रात जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। चंद्रगुप्त माइंस के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल हो गया और दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधी का इलाज हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि बाइक सवार अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना से इलाके में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर केरेडारी थाना पुलिस ने इलाके में वाहन जांच और घेराबंदी शुरू की। इसी दौरान चंद्रगुप्त माइंस कंपनी के पास पुलिस का सामना संदिग्ध बाइक सवारों से हुआ।

रुकने के बजाय पुलिस पर की फायरिंगः बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब संदिग्धों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे पुलिस ने मौके से दबोच लिया, जबकि दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

बार-बार बदल रहे हैं अपनी पहचानः पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों पकड़े गए आरोपी पूछताछ के दौरान बार-बार अपना नाम और पहचान बदल रहे हैं। उनकी वास्तविक पहचान, आपराधिक इतिहास और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में पुलिस गहन पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने की मुठभेड़ की पुष्टिः केरेडारी थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने फोन पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा पूरे मामले की जांच जारी है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि गिरोह के अन्य सदस्य भी आसपास के क्षेत्र में छिपे हो सकते हैं। पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की पहचान और बरामद हथियारों के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। उम्मीद है कि पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा करेगी।

ट्रक की अवैध नीलामी मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को झटका

कोर्ट ने ट्रक मालिक को दो सप्ताह के भीतर वाहन लौटाने और 3 लाख मुआवजा देने का दिया निर्देश

संवाददाता

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रक की अवैध नीलामी मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रक मालिक को दो सप्ताह के भीतर वाहन लौटाने और 3 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने के लिए निर्धारित 60 दिनों की वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले ही ट्रक की नीलामी कर दी, जो कानून के विरुद्ध है। साथ ही वाहन मालिक को व्यक्तिगत नोटिस भी नहीं दिया गया।

अदालत ने माना कि प्रशासन की जल्दबाजी और गैर-कानूनी कार्रवाई से ट्रक मालिक को मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता अधिक मुआवजे की मांग करना चाहता है, तो वह सक्षम सिविल कोर्ट में दावा कर सकता है।

रात 12:01 बजे से लागू होगा वो 'गुप्त नियम'.. डोनाल्ड ट्रंप के एक सीक्रेट फैसले से हिली दुनिया

भारत अब बड़े संकट में फंसने वाला है?

नई दिल्ली/एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अचानक लिए गए फैसले ने वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया है। शुक्रवार रात 12:01 बजे से एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा है, जिसे लेकर कयासों और आशंकाओं का बाजार गर्म हो चुका है। पर्दे के पीछे से जारी इस आदेश के बाद पूरी दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन पर टिकी हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिकी प्रशासन के इस एक बड़े दांव से भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षेत्र पर कोई गहरा संकट मंडराने वाला है?

एक बड़ी घटनाक्रम में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और 16 अन्य देशों से आयातित सामान पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। यह कदम ऐसे सामान के उत्पादन में जबरदस्ती मजदूरी के इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों के तहत उठाया गया है। पिछले महीने, जब अमेरिका ने ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत टैरिफ का प्रस्ताव रखा था, तो भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा गया था जिन पर 12.5 प्रतिशत लेवी (शुल्क) लगनी थी। लेकिन वाशिंगटन ने नई दिल्ली द्वारा अपनी विदेश व्यापार नीति में किए गए उस संशोधन पर ध्यान दिया, जिसमें जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाई गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इस मुद्दे पर जारी एक मेमोरेंडम में कहा, इन कदमों के परिणामस्वरूप, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे सलाह दी है कि इन अर्थव्यवस्थाओं के सामान पर 10 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसी रोक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और प्रोत्साहित किया जा सके।

शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका : जेमिसन ग्रीर ने 60 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा कीः अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने गुरुवार को ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की। यह घोषणा सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त लेवी की समय-सीमा खत्म होने से एक दिन पहले की गई।

जिन देशों में जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान पर रोक लगाने वाले कानून नहीं हैं - जैसे चीन, यूनाइटेड किंगडम और जापान - उन्हें 12.5 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। जबरदस्ती मजदूरी से जुड़े टैरिफ उन कच्चे माल पर लागू नहीं होंगे जिनकी घरेलू आपूर्ति की कमी हो सकती है; उन उत्पादों पर नहीं जिनसे पूरी अर्थव्यवस्था में व्यवधान पैदा हो सकता है; और उन उत्पादों पर भी नहीं जिनका उत्पादन या खेती अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा सकती।

टैरिफ का सामना कर रहे 60 देशों में से 17 देशों पर 10 प्रतिशत की दर लागू होगी, जिनमें भारत, कनाडा, यूके, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। बाकी 43 देशों को 12.5 प्रतिशत टैरिफ देना होगा।

कहा गया है कि ग्रीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर, 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ लगाने का अंतिम कदम उठाया है। यह कार्रवाई जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी विफलता के कारण की गई है।

शुक्रवार रात 12:01 बजे से नई टैरिफ लागू होंगीः नई टैरिफ शुक्रवार रात 12:01 बजे से लागू होंगी, ठीक उसी समय जब 10 प्रतिशत का अस्थायी इंपोर्ट टैक्स खत्म हो रहा है। यह कदम फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया था जिसमें अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई रेलिबरेशन डेर टैरिफ को रद कर दिया गया था।

ग्रीर ने यहां एक बयान में कहा कि यह कदम मानवाधिकारों के उल्लंघन और व्यापार के गलत तरीकों, दोनों को ठीक करने की दिशा में काम करेगा, ताकि हर जगह कामगारों का भला हो सके। इस संबंध में एक फेडरल नोट में इस बात का ज़िक्र किया गया कि जून में प्रस्तावित टैरिफ की घोषणा के बाद भारत ने जबरन मजदूरी से जुड़े सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया।

न्यूज IN ब्रीफ

कन्हर सरसो तेल कंपनी से कथित ठगी मामले में दो सगे भाइयों पर वारंट

चतरा : हजारीबाग जिले के डेमोटांड में स्थापित कन्हर सरसो तेल कंपनी से एक लाख रु की कथित ठगी के मामले में चतरा व्यवहार न्यायालय ने दो सगे भाइयों के खिलाफ वारंट जारी किया है।आरोपियों की पहचान चतरा जिले के सिमरिया हनुमान भंडार के संचालक एवं गोवा खुर्द निवासी नवनीत कुमार उर्फ बिरजू सिंह और मनोज सिंह के रूप में हुई है।न्यायालय ने मामले के अनुसंधानकर्ता सदर थाना के पुलिस पदाधिकारी टीपू अंसारी को दोनों आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी का निर्देश दिया है।आरोप है कि दोनों भाइयों ने कन्हर तेल कंपनी के खाते से चेक चोरी कर धोखे से बैंक ऑफ इंडिया, सिमरिया शाखा से एक लाख रुपये की निकासी की। इस मामले में कन्हर तेल कंपनी के संचालक संतोष सिंह ने जनवरी 2026 में सदर थाना में कांड 01/2026 दर्ज कराया था। पुलिस अनुसंधान में आरोपों की पुष्टि होने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। अब पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में जुट गई है।

चतरा में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन

चतरा : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निदेर्शानुसार गुरुवार को विकास भवन स्थित नया कचहरी, चतरा में जिला कांग्रेस कमिटी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, लगातार हो रहे पेपर लीक, छात्रों पर हुए पुलिस दमन तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन समर्पित किया गया।धरना-प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमिटी, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, इंटक, महिला कांग्रेस, सेवादल, विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, कांग्रेस कार्यकताओं, छात्र-छात्राओं, युवाओं तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं ने करोड़ों छात्रों और युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है। छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में हुई। अनियमितताओं पर संसद में विशेष चर्चा तथा छात्रों एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज सभी एफआईआर एवं आपराधिक मामलों को वापस लेने की मांग की वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी तथा शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।कार्यक्रम का समापन जिला अध्यक्ष चंद्रदेव गोप के नेतृत्व में उपायुक्त चतरा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के साथ हुआ।

हजारीबाग के कोयला परिवहन पर चतरा मार्ग से रोक की मांग

चतराः झामुमो ने हजारीबाग जिले से होने वाले कोयला परिवहन को चतरा जिले के रास्ते संचालित किए जाने का विरोध तेज कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय सदस्य मनोज कुमार चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 9 अगस्त से 'हाइवा चतरा छोड़ो' आंदोलन शुरू किया जाएगा।ज्ञापन में कहा गया है कि हजारीबाग स्थित एनटीपीसी परियोजना से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कोयले की ढुलाई चतरा जिले के टंडवा, सिमरिया, चतरा और गिद्धौर मार्ग से की जा रही है। संगठन का आरोप है कि कम दूरी का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद लंबे रास्ते का उपयोग किया जा रहा है, जिससे चतरा की सड़कों पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसके कारण सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, धूल और प्रदूषण बढ़ रहा है तथा आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।झामुमो ने ज्ञापन में यह भी कहा कि खनन से मिलने वाला राजस्व और रॉयल्टी हजारीबाग जिले को प्राप्त होती है, जबकि उसके दुष्प्रभाव चतरा की जनता को झेलने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी टंडवा एवं केटीपीसी बंडेडीह से फ्लाई ऐश की ढुलाई में भी नियमों के पालन की मांग करते हुए पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही गई।

पार्टी ने मांग की है कि हजारीबाग के कोयले का परिवहन उसी जिले के निर्धारित मार्गों से कराया जाए। चतरा होकर हजारीबाग लौटने वाले हाइवा वाहनों का परिचालन बंद किया जाए, फ्लाई ऐश की ढुलाई नियमानुसार कराई जाए, प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा और रोजगार मिले तथा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए। साथ ही कोयला परिवहन में स्थानीय वाहन मालिकों और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की भी मांग उठाई गई।

झामुमो ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 9 अगस्त 2026 से सिमरिया के सुभाष चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा और हजारीबाग से चतरा मार्ग होकर गुजरने वाले कोयला वाहनों के परिचालन का विरोध किया जाएगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्य सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई है। इस अवसर पर झामुमो के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

सक्किम सुरंग हादसा : रोजगार की तलाश में गए रनिया के युवक की मौत, चार दिन बाद गांव पहुंचा शव, पूरे इलाके में मातम

संवाददाता

खूंटी: झारखंड में बेरोजगारी के कारण रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने वाले मजदूरों की जिंदगी कितनी असुरक्षित हो सकती है, इसका दर्दनाक उदाहरण सिक्किम में हुए सुरंग हादसे ने सामने ला दिया है। सिक्किम के नामची जिला अंतर्गत समरडुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता स्टेज-6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन हेड रेस टनल में गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट में रनिया प्रखंड के डाहु गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्णा साहू, बुदडु विकास कडुलना तथा पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड के कुमसिंग मदुरा गांव निवासी 48 वर्षीय मसीह बरजो सुरंग के अंदर दब गए थे। घटना सोमवार 20 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे हुई। हादसे की सूचना पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मियों ने मजदूरों के परिजनों को दी, जिसके बाद तीनों परिवारों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही परिजन सिक्किम के लिए रवाना हो गए। हादसे के बाद पूरे डाहु गांव समेत आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

हादसे में जान गंवाने वाले तीनों मजदूर अपने-अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। मृतक विकास कडुलना और मसीह बरजो के तीन-तीन छोटे बच्चे हैं, जिनके सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों और परिजनों ने राज्य सरकार से आर्थिक सहायता तथा मृतकों के परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। साथ ही शवों को उनके गांव तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने की गुहार लगाई थी।

हादसे के बाद राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद सबसे पहले कृष्णा साहू का शव सुरंग से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद पटेल इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से एंबुलेंस के

माध्यम से कृष्णा का शव सिक्किम से उसके पैतृक गांव डाहु भेजा गया।

शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे, हादसे के चार दिन बाद जैसे ही एंबुलेंस गांव पहुंचा, पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। शव देखते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए।

कृष्णा का शव लेकर उसका छोटा भाई बबलू साहू और दो अन्य साथी गांव पहुंचे। बबलू ने बताया कि वह भी पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के मेस में कार्यरत है। उसने बताया कि कंपनी की ओर से तत्काल सहायता के रूप में 50 हजार रुपये दिए गए हैं।

परिजनों के अनुसार, कृष्णा साहू महज एक माह पहले ही रोजगार की तलाश में सिक्किम गया था। और निर्माणाधीन सुरंग में मजदूरी कर रहा था। बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर घर से निकला कृष्णा अब ताबूत में लौटकर आया।

बेरोजगारी और पलायन पर फिर उठे सवालः इस हादसे ने एक बार फिर झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में हो रहे मजदूरों के पलायन की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर होते तो शायद इन युवकों को हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूरी नहीं करनी पड़ती।ढवहीं, विकास कडुलना और मसीह बरजो के शवों को निकालने का अभियान भी जारी है। परिजन लगातार प्रशासन और कंपनी से सुरक्षित रेस्क्यू तथा उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

सड़क निर्माण की आस में ग्रामीणों ने की भगवान की पूजा, बोले

अब सरकार नहीं, ईश्वर से ही उम्मीद

संवाददाता

खूंटी : खूंटी जिले के घाघरा बांघटोली मोड़ से विचना जाने वाली जर्जर सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। वर्षों से सड़क निर्माण नहीं होने और जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं होने से निराश ग्रामीणों ने सड़क किनारे पूजा-अर्चना कर भगवान से सड़क निर्माण की प्रार्थना की। घाघरा गांव के पहान रावकान पहान ने वैदिक विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों का आवागमन कठिन हो गया है। बरसात के दिनों में यह मार्ग और भी खतरनाक बन जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूजा कार्यक्रम में गनालोया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल

गंझू ग्राम प्रधान फागू मुंडा, ग्राम सभा सचिव प्रसून कुमार मांझी, छत्रपाल नाथ, शिव कुमार महतो, चैतु पहान, सुखराम मुंडा, जेठू कम्हार, बलदेव मुंडा, विरसा पहान सहित घाघरा गांव के बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार सड़क निर्माण की मांग जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के समक्ष रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अब सरकार से उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले तथा जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण की दिशा में पहल नहीं हुई तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे।

ज्वेलर्स व वाइन शॉप चोरी कांड का खुलासा चार अभियुक्त जमशेदपुर से गिरफ्तार

संवाददाता

तोरपा (खूंटी): तोरपा थाना क्षेत्र स्थित मां शांति ज्वेलर्स एवं एक विदेशी शराब दुकान में हुई चोरी की घटना का खूंटी पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सफल उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने मामले में चार अभियुक्तों को जमशेदपुर से गिरफ्तार करते हुए चोरी गई चांदी के आभूषण, कई पेटी महंगी विदेशी शराब तथा घटना में प्रयुक्त शटर काटने का औजार को बरामद किया है। चोरी किए गए सामानों में से अधिकांश सामान चांडिल क्षेत्र से बरामद किए गए हैं, जबकि कुछ विदेशी शराब अभियुक्तों द्वारा उपयोग कर ली गई थी। जानकारी के अनुसार, अभियुक्तों ने तोरपा बाजार स्थित मां शांति ज्वैलर्स और एक विदेशी शराब दुकान का शटर व ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद वे

लाखों रुपये मूल्य के चांदी के आभूषण और कई पेटी विदेशी शराब लेकर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस टीम ने पश्चिम सिंहभूम और जमशेदपुर में छापेमारी करते हुए चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सभी अभियुक्तों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तार अभियुक्तों में दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार, मोहम्मद अफरोज, बाबू पिल्ले तथा अजय शर्मा शामिल हैं। सभी अभियुक्त जमशेदपुर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है।

पुलिस ने चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस त्वरित कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने खूंटी पुलिस की सराहना की है।

वंशिका राज ने नीट यूजी में किया शानदार प्रदर्शन

समाजसेवी नीतीश कुमार ने कलम और शॉल भेंटकर किया सम्मानित

संवाददाता

चतरा : जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड क्षेत्र के खापलवानी गांव निवासी शिव कुमार सिंह की सुपुत्री वंशिका राज ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) में शानदार प्रदर्शन करते हुए 626 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 4174 हासिल की है। वंशिका राज की इस शानदार उपलब्धि पर समाजसेवी नितीश कुमार ने उनके घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने वंशिका को कलम एवं शॉल भेंट कर उनकी सफलता के

लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वंशिका ने अपनी मेहनत, लगन, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समाजसेवी नितीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने की क्षमता रखती हैं।आवश्यकता है तो केवल सही दिशा, निरंतर मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प की। वंशिका राज ने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यदि विद्यार्थी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। वंशिका राज की सफलता उनके माता-पिता और परिवार के लिए भी गौरव का विषय है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल खापलवानी गांव, बल्कि पूरे कान्हाचट्टी प्रखंड का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता क्षेत्र के उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं।वंशिका की इस सफलता पर परिजनों, शुभचिंतकों, ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वंशिका राज आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और सेवाभाव के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र की सेवा करेंगी तथा अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम और भी गौरवान्वित करेंगी।

आम्रपाली में नियमों के विपरीत कोयले का उत्पादन और डिस्पैच

श्रमिक संगठन एटक के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डीजीएमएस को लिखा पत्र

संवाददाता

चतरा : जिले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के आम्रपाली परियोजना में कोयला उत्पादन और डिस्पैच में लगे एनसीसी कंपनी का मामला दिन प्रतिदिन विवाद गहराते जा रहा है। श्रमिक संगठन के एटक के जॉइंट सेक्रेटरी विनोद बिहारी पासवान ने डीजीएमएस को पत्र लिखकर नियमों का उल्लंघन कर कोयले का उत्पादन और डिस्पैच करने का मामला उजागर करते हुए पत्र प्रेषित किया है। बताया गया है कि कोयल का उत्पादन का सही मेजरमेंट नहीं किया जा रहा है जिससे भारी मात्रा में हेराफेरी और घोटाले का संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा है कि नियमों के विपरीत जाकर कोयले का डिस्पैच शिवपुर साइडिंग में एनसीसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि डीएमएस के अधिकारियों के द्वारा एनसीसी कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई किया जाता है। एनसीसी कंपनी के ऊपर युवाओं से पैसा लेकर बहाली करने का मामला तथा माइंस के नजदीक घरों को बिना विस्थापित किए हुए हैवी ब्लास्टिंग कर क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने का मामला भी सक्षम प्राधिकार के पास शिकायत कई लोगों ने किया है।

संसद में गूंजा टंडवा-सिमरिया का कोयला परिवहन मुद्दा

सांसद कालीचरण सिंह ने सरकार से मांगा समर्पित कोल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर

संवाददाता

चतरा : चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह ने संसद के मानसून सत्र में नियम 377 के तहत जिले के टंडवा, सिमरिया और आसपास के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में अनियंत्रित कोयला परिवहन से उत्पन्न गंभीर जनसमस्याओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आम यातायात से अलग समर्पित कोल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की मांग करते हुए कहा कि विकास के साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

सांसद ने सदन में कहा कि टंडवा, सिमरिया, चतरा और गिद्धौर क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी वाहन कोयले की ढुलाई करते हैं। इन वाहनों के कारण प्रमुख सड़कों पर दिन-रात यातायात का दबाव बना रहता है, जिससे जाम, सड़क दुर्घटनाएं और आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों, मरीजों, कर्मचारियों और छोटे वाहन चालकों पर पड़ रहा है, जिन्हें घंटों जाम में फंसना पड़ता है।

धूल-प्रदूषण से बिगड़ रही लोगों की सेहतः सांसद ने कहा कि भारी वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली कोयले की धूल आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

कृषि और जलस्रोतों पर भी पड़ रहा असरः कालीचरण सिंह ने कहा कि कोयला

परिवहन का असर केवल यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि और पर्यावरण भी इसकी चपेट में हैं। सड़कों के किनारे जमा कोयले की धूल बारिश के दौरान जलस्रोतों तक पहुंचकर प्रदूषण बढ़ा रही है। वहीं खेतों पर धूल की परत जमने से कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, जो क्षेत्र के किसानों के लिए चिंता का विषय है।

रेल और कन्वेयर बेल्ट को मिले प्राथमिकताः सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की कि कोयले की ढुलाई के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करते हुए रेल नेटवर्क, कन्वेयर बेल्ट और अन्य आधुनिक एवं प्रदूषण-मुक्त परिवहन प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाओं, जाम और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य शिविर की मांगः सांसद ने प्रभावित क्षेत्रों में नियमित पानी का छिड़काव, कोयला ढोने वाले वाहनों को ढककर परिवहन, प्रदूषण की नियमित निगरानी और पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने तथा श्वसन संबंधी बीमारियों के उपचार की विशेष व्यवस्था करने की भी आवश्यकता बताई।

विकास के साथ जनहित का भी होसंरक्षणः सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोयला उत्पादक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन विकास की कीमत स्थानीय लोगों को प्रदूषण, दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संकट के रूप में नहीं चुकानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से टंडवा और आसपास के क्षेत्रों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की। उनका कहना था कि समर्पित कोल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन व्यवस्था, प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से ही विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

सुनील मुंडा को हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल, जमानत याचिका खारिज

सुनील मुंडा के खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में पहले से भी दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

मेट्रो रेज

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने और लेवी वसूली के आरोपी सुनील मुंडा उर्फ भारत जी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला बुढ़मू थाना कांड संख्या 03/2025 से संबंधित है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुनील मुंडा पर ठेकेदारों और व्यवसायियों से रंगदारी (लेवी) वसूलने, प्रतिबंधित उग्रवादी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहने तथा संगठन के लिए काम करने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने उसे कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया था।

डोरंडा-नामकुम पथ चौड़ीकरण से जुड़े मुआवजा मामले में हुई सुनवाई

रांचीः डोरंडा-नामकुम पथ चौड़ीकरण से जुड़े मुआवजा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट के आदेश पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सशरीर उपस्थित हुए, लेकिन भू-अर्जन से जुड़े मूल दस्तावेज और अवॉर्ड पेश नहीं किए गए।

सरकार के हलफनामे से असंतुष्ट अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से सरकारी अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठता है। कोर्ट ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आगामी सोमवार को मूल दस्तावेज और अवॉर्ड के साथ फिर से सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। यह मामला 13 साल पुराने भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

जांच एजेंसियों का दावा है कि विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इसी आधार पर अदालत में जमानत का विरोध किया गया।

मामले की सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया मामले की प्रकृति गंभीर है और इस स्तर पर आरोपी को राहत देना उचित नहीं होगा। जानकारी के अनुसार, सुनील मुंडा उर्फ भारत जी के खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

24 जुलाई डोमिसाइल दिवस

खतियान आधारित लागू हो स्थानीय नीति : शिवा कच्छप

मेट्रो रेज

रांचीः केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के तत्वावधान में डोमिसाइल आंदोलन समर्थको ने आंदोलन में शहीद हुए संतोष कुंकल, विनय तिग्गा, कैलाश कुजूर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। मेकॉन कालोनी स्थित त्रिमूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। ।

केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि डोमिसाइल दिवस 24 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन है। आदिवासी मूलवासी जनता की भावना के अनुरूप खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर जो संघर्ष हुआ, वह अविश्वसनीय है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता के उस संघर्ष को आज भी जीवित रखा है, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करके ही आदिवासी मूलवासी जनता दम लेगी। इसके लिए अलग-अलग जगहो पर अलग-अलग नेतृत्वकर्ता के मध्यम से राज्यव्यापी आंदोलन चलाने की आवश्यकता है । 24 साल हो गए, लेकिन स्थानीय नीति तय नही हो पाया है। हमारे युवा लोग नौकरी और रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे है। जिस मांग को

लेकर हमारे लोगो ने अपनी प्राण की आहूति दी। उनका सपना आज भी अधूरा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप उपस्थित दिनेश उरांव, धरमू उरांव, सुनिल गाडी,भोला तिर्की, संगीता गाड़ी,सिटीया उरांव, रिता खलखो, , नुरी तिर्की, सती तिर्की, अनिता उरांव, पिंकी कुजूर, पर्वती टोप्पो व अन्य शामिल थे।

रिनपास के विकास के लिए 25 करोड़ स्वीकृत, विभाग ने जारी किया आदेश

संवाददाता

रांची : झारखंड सरकार ने रांची स्थित रिनपास के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

सरकार के अनुसार, इस राशि का उपयोग रिनपास में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, नए भवनों के निर्माण, पुराने भवनों के जीर्णोद्धार और नई मशीनों व जरूरी उपकरणों की खरीद में किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए शासी परिषद की मंजूरी लेना जरूरी होगा।

आवंटित राशि में 10 करोड़ 19 लाख 48 हजार 60 रुपये गैर-वेतन मद के लिए बैंक खाते के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। वहीं 3 करोड़ 80 लाख 51 हजार 940 रुपये वेतन मद के लिए दिए गए हैं। जबकि 11 करोड़ गैर-वेतन मद में पीएल खाते के माध्यम से खर्च किए जाएंगे।

सरकार ने रिनपास की निदेशक जयाति सिमलाई को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाया है। सरकार ने राशि के उपयोग को लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित अभियंताओं की होगी।

खर्च की राशि का नियमित ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही हर महीने की 10 तारीख तक खर्च और कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजनी होगी।

राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, नन्हें खिलाड़ियों ने दिखाया दम

संवाददाता

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का गुरुवार को रांची के खेलगांव स्थित प्रैक्टिस मैदान में भव्य शुभारंभ हुआ। 23 से 25 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से कक्षा 3 से 5 तक के बालक और बालिका खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य कम उम्र में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

प्रतियोगिता का उद्घाटन घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने किया। इस अवसर पर झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, पुष्पा हसा, ऋतुराज और मोहित अवस्थी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर किया।

मुख्य अतिथि सोमेश चंद्र सोरेन ने पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह शिक्षा की शुरूआत शुरूआती स्तर से होती है, उसी प्रकार खेलों के लिए भी एक मजबूत स्पोर्ट्स नर्सरी तैयार करने की जरूरत है। जिससे कि बचपन से ही प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके।

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि कई बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन उन्हें अवसर और मंच नहीं मिल पाता। लिटिल चैंप्स प्रतियोगिता ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान कर रही है।

धीरसेन ए सोरेंग ने कहा प्रतिभा जन्म से नहीं, अवसर मिलने से निखरती है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का प्रयास है कि राज्य के हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। कम उम्र में खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

बालक-बालिकाओं ने खेल में दिखाया दमः पहले दिन बालिका वर्ग के मुकाबले खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में खेले गए। इसमें गुमला ने गोड्डा को 6-0, रामगढ़ ने कोडरमा को 2-0, सिमडेगा ने खूंटी को 3-0, लोहरदगा ने चतरा को 3-0, पलामू ने जामताड़ा को 6-0 और साहिबगंज ने धनबाद को 3-1 से हराया। रांची और सरायकेला के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद टाईब्रेकर में रांची ने 12-11 से जीत दर्ज की।

बालक वर्ग के मुकाबले सीएम एक्सीलेंस स्कूल बरियातू मैदान में खेले गए। यहां गुमला ने कोडरमा को 9-0, चतरा ने हजारीबाग को 1-0, खूंटी ने बोकारो को 9-0, गोड्डा ने कोडरमा को 6-1 और सरायकेला ने चतरा को 3-2 से मात दी। खूंटी के खिलाड़ी रितिक ने बोकारो के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक सहित पांच गोल दागे। आयोजन को सफल बनाने में राज्य खेल कोषांग और आयोजन समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट-2026 का समापन, रांची बना ओवरऑल चैंपियन

मेट्रो रेज

रांचीः कांके रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन में आयोजित तीन दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट-2026 का शुक्रवार, 24 जुलाई को समापन हो गया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रांची जिला लगातार ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि गुमला ने दूसरा और खूंटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

व्यक्तिगत प्रदर्शन में रांची की दारोगा मनीषा कुमारी को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। वहीं खूंटी जिले के कांस्टेबल-77 मनमोहन कृष्णा को रनर-अप का सम्मान मिला।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि एडीजी मनोज कौशिक ने विजेता टीम रांची को ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। रनर-अप टीम को एसएसपी राकेश रंजन ने सम्मानित किया, जबकि व्यक्तिगत विजेताओं को सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए।

100 प्रतिभागियों ने लिया हिस्साः 22 से 24 जुलाई तक आयोजित इस क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन भी एडीजी मनोज कौशिक ने किया था। प्रतियोगिता में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों के लगभग 100 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन सीआईडी द्वारा किया गया।

मुख्य अतिथि मनोज कौशिक ने विजेता टीमों और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि पुलिस ड्यूटी मीट का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों की अनुसंधान क्षमता, वैज्ञानिक सोच और व्यावहारिक दक्षता को और बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अनुसंधान की बारीकियों को समझने और प्रस्तुत करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया,

जिससे अन्य पुलिसकर्मियों को भी सीखने और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

कई विषयों पर हुई परीक्षाः पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान प्रतिभागियों की अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता से जुड़े विभिन्न विषयों पर परीक्षा ली गई। इसमें विधि-विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस), कानून, घटनास्थल से साक्ष्य उठाने, पैकिंग एवं फॉरवर्डिंग की प्रक्रिया, फिंगरप्रिंट, घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी, मेडिको-लीगल, ऑब्जर्वेशन टेस्ट तथा पुलिस पोर्ट्रेट जैसे विषय शामिल थे।

इसके अलावा स्वान दस्ता (डॉग स्क्वायड) के अंतर्गत ट्रैकर डॉग एवं एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग प्रशिक्षण, कंप्यूटर अवेयरनेस तथा स्पेशल ब्रांच से संबंधित विषयों पर भी प्रतिभागियों की परीक्षा आयोजित की गई।

ये रहे मौजूदः प्रतियोगिता के परीक्षक के रूप में जिला बल के इंस्पेक्टर असीत मोदी, सीआईडी के इंस्पेक्टर नीरज सहाय और अमित कुमार ने जिम्मेदारी निभाई।

समापन समारोह में एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के डीएसपी, सार्जेंट मेजर आनंद खलखो, सभी सार्जेंट तथा जिला बल के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग
E-mail: rdsdhazaribagh@gmail.com

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के द्वारा आमंत्रित अल्पकालीन ई0 निविदा आमंत्रण सूचना संख्या **RDSPL/SD/HZB/16/2026-27** पी0आर0 संख्या 385239 Rural Development(26-27).D के online प्रकाशित निविदा के ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0 – 9934523795 पढ़ा जाय।

निविदा की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल
हजारीबाग

PR 385702 Rural Development(26-27)#D

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।
(महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग)
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
(जिला बाल संरक्षण इकाई)
Email Id –dcpsramgarh@gmail.com

–: आम सूचना :–

विभागीय अधिसूचना संचिका सं0 526/SP–POCSO/JSCPS/2023–24 & 2685, राँची दिनांक 24.10.2024 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों का चयन हेतु प्राप्त कुल 17 आवेदनों में से वांछनीय अहर्त्ता पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 10 पाया गया, जिन्हें दिनांक 20.07.2026 अपराहन् 02:00 बजे जिला स्तरीय गठित चयन समिति, रामगढ़ द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। चयन समिति, रामगढ़ द्वारा साक्षात्कार के उपरांत वांछनीय अहर्त्ता पूर्ण करने वाले उपस्थित 07 उम्मीदवारों में से 05 उम्मीदवारों को सहायक व्यक्ति के लिए पैनल निर्माण हेतु अनुशंसा प्रदान की गई, जिसकी सूची रामगढ़ के वेबसाइट ramgarh.nic.in एवं जिला सूचना एवं जन संपर्क विभाग (PRD) के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापन में देखी जा सकती है।

चयन समिति, रामगढ़ द्वारा अनुशंसित सहायक व्यक्तियों का पैनल तीन वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा, जिनके कार्यो की समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्यिों के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के अपराधिक चरित्र का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा करवाना अनिवार्य होगा, यदि किसी भी सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाना में कोई अपराधिक मामला दर्ज पाया जायेगा, तो उनके खिलाफ विधिक कारवाई की जा सकती है तथा सूचीबद्धता रद्द की जा सकती है।

ह0/–
सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग, रामगढ़।

PR 385703 District(26-27)D

सूक्ति

सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर

पेपर लीक, युवा आक्रोश और समाधान

भारत आज विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकीय आकलनों के अनुसार देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, जबकि लगभग 27-28 प्रतिशत आबादी 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में आती है। यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी संपदा है और विकसित भारत के लक्ष्य की सबसे मजबूत आधारशिला भी। हर वर्ष देशभर में लगभग दो से ढाई करोड़ युवा नीट, जेईई, सीयूईटी, यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, रेलवे तथा विभिन्न राज्यों की भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इन परीक्षाओं के साथ केवल रोजगार या उच्च शिक्षा का अवसर नहीं जुड़ा होता, बल्कि करोड़ों परिवारों की आशाएं, वर्षों की मेहनत और आर्थिक संसाधन भी जुड़े होते हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो जाता है या भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक अधर में लटक जाती है, तो सबसे गहरी चोट युवाओं के विश्वास पर पड़ती है। बीते कुछ वर्षों में देश के अनेक राज्यों में सामने आए पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में प्रश्नपत्र लीक और संगठित नकल के मामले सामने आए। वर्ष 2024 की नीट-यूजी परीक्षा को लेकर भी पूरे देश में व्यापक बहस हुई और जांच केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंची। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि परीक्षा प्रणाली सुरक्षित और पारदर्शी नहीं होगी तो प्रतिभाशाली युवाओं का मनोबल कमजोर होगा और योग्यता आधारित व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी प्रभावित होगा। हिमाचल प्रदेश भी इस चुनौती से अछूता नहीं रहा। वर्ष 2022 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और मामला सीबीआई को सौंपा गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच के दौरान कई परीक्षाओं में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का निर्णय लिया। यह घटना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं भी, बल्कि इस बात का संकेत भी थी कि भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इन घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 लागू किया। इस कानून का उद्देश्य संगठित परीक्षा माफिया पर कठोर कार्रवाई करना, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना तथा सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करना है। इसके साथ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सुधारों की दिशा में भी पहल की गई। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2025 लागू करते हुए पेपर लीक को गैर-जमानती अपराध बनाया तथा दोषियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के समर्थन में चल रहे आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जन्म दिया। आंदोलन की प्रमुख मांग परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर प्रभावी रोक और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। जब लाखों युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल हों, तब उनकी आवाज को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक शासन की जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए।

यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एनटीए और पेपर लीक जैसे मामले नहीं सुलट पा रहे हैं तो उन्हें पद की गरिमा बनाए रखते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। दूसरे यह समय आंदोलनरत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करने का नहीं है, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था विकसित करने का है जिसमें प्रश्नपत्र लीक होना लगभग असंभव हो जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक सुधारों का समन्वय आवश्यक है। प्रश्नपत्रों के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल एन्क्रिप्शन, बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा केंद्रों की रियल-टाइम म्यॉनिटरिंग, परीक्षा माफिया की अवैध संपत्ति की जब्ती, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक न्यायालय जैसी व्यवस्थाएं परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बना सकती हैं। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की स्पष्ट जवाबदेही भी तय होनी चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर हुई लापरवाही का उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके। राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि युवाओं का भविष्य चुनावी नारों का विषय नहीं हो सकता। पेपर लीक किसी एक राज्य, किसी एक सरकार या किसी एक राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश के युवाओं के विश्वास, प्रशासनिक विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख का विषय है। इसलिए सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका, प्रशासन, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज- सभी को मिलकर ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। भारत के अमृतकाल में सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हर युवा को यह भरोसा मिले कि उसकी मेहनत का मूल्यांकन केवल उसकी योग्यता के आधार पर होगा, न कि किसी भ्रष्ट नेटवर्क की वजह से। लोकतंत्र की असली शक्ति विरोध और दमन में नहीं, बल्कि संवाद, जवाबदेही, पारदर्शिता और निरंतर सुधार में निहित है। यदि सरकारें सुधार के प्रति प्रतिबद्ध रहें, संस्थाएं निष्पक्षता बनाए रखें और जन-आंदोलन समाधानमुखी बने रहें, तो न केवल पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा, बल्कि देश का युवा भी पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। शिक्षित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त युवाओं से ही विकसित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।

ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं स्मार्ट भंडारण भी जरूरी

'उत्पादन और खपत के बीच संतुलन बनाए रखना ही विद्युत तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था। यही कारण था कि नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा, की सबसे बड़ी सीमा उसकी अनियमित उपलब्धता थी। लेकिन आज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीइएसएस) पंप स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकों ने इस दशकों पुरानी अवधारणा को बदलना शुरू कर दिया है।'

सूर्य से बिजली बनाना अब उपलब्धि नहीं, उसे सूर्यास्त के बाद भी उपलब्ध कराना नई ऊर्जा क्रांति है। भारत की ऊर्जा यात्रा आज ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। पिछले एक दशक में देश ने सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, लेकिन अब ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा परिवर्तन उत्पादन से आगे बढकर ऊर्जा भंडारण की दिशा में दिखाई दे रहा है। यही परिवर्तन भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के एक नए युग में ले जाने की क्षमता रखता है। कुछ वर्ष पहले तक विद्युत अभियांत्रिकी का एक स्थापित सिद्धांत था कि बड़े पैमाने पर बिजली का आर्थिक और व्यावहारिक भंडारण संभव नहीं है। इसलिए जितनी बिजली उत्पन्न होती थी, उसका लगभग उसी समय उपयोग करना आवश्यक होता था। उत्पादन और खपत के बीच संतुलन बनाए रखना ही विद्युत तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था। यही कारण था कि नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा, की सबसे बड़ी सीमा उसकी अनियमित उपलब्धता थी। लेकिन आज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीइएसएस) पंप स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकों ने इस दशकों पुरानी अवधारणा को बदलना शुरू कर दिया है। ऊर्जा का भविष्य अब केवल उत्पादन में नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित, स्मार्ट और दीर्घकालिक भंडारण में भी निहित है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश की स्थापित गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता 240 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, जिसमें लगभग 110 गीगावाट सौर और 55 गीगावाट पवन ऊर्जा का योगदान है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादक नहीं, बल्कि विश्वसनीय हरित ऊर्जा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में भी अग्रसर है। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यह रही कि सूर्य दिन में ऊर्जा देता है, जबकि बिजली की सर्वाधिक मांग प्रायः शाम और रात्रि के पीक आवर्स में होती है। अब तक इस अंतर को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र पूरा करते रहे हैं। लेकिन अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीइएसएस) इस चुनौती का प्रभावी समाधान बनकर उभरा है। दिन में सौर संयंत्रों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को बैटरियों में सुरक्षित रखकर आवश्यकता के समय उपयोग किया जा सकता है। इससे कोयला आधारित उत्पादन पर निर्भरता घटेगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्रिड अधिक स्थिर बनेगा और उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय बिजली उपलब्ध होगी। स्पष्ट है कि ऊर्जा क्षेत्र का अगला चरण अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि स्मार्ट भंडारण है। इस परिवर्तन की झलक अब राज्यों की परियोजनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। राजस्थान, जो पहले ही देश की सौर ऊर्जा राजधानी के रूप में स्थापित हो चुका है, अब ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। हाल ही में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरइआरसी) द्वारा बीकानेर के पूगल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट सौर परियोजना के साथ 1600 मेगावाट/6400 मेगावाट-घंटा क्षमता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारण तंत्र (बीइएसएस)को स्वीकृति देना इसी दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि दिन में उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बैटरियों में संचित कर शाम और रात्रि के पीक आवर्स में उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। यह केवल राजस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत की हरित ऊर्जा नीति अब उत्पादन के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण आधारित बिजली व्यवस्था की ओर निर्णायक रूप से बढ़ रही है। यदि बैटरी ऊर्जा को कुछ घंटों के लिए सुरक्षित रखती है, तो ग्रीन हाइड्रोजन उसे लंबे समय तक संरक्षित रखने का माध्यम बन सकता है। यही कारण है कि इसे भविष्य का हरित ईंधन कहा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण पानी के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसमें ऊर्जा का स्रोत सौर और पवन जैसी नवीकरणीय बिजली होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है और ऑक्सीजन उपयोगी उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है।

इस तकनीक ने जल की उपयोगिता को भी नया आयाम दिया है। जिस जल को अब तक हम मुख्यतः पेयजल, सिंचाई और जलविद्युत के संदर्भ में देखते रहे, वही भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत भी बन सकता है। अर्थात सूर्य, जल और हरित तकनीक का यह समन्वय ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति का आधार बन रहा है। भारत ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी, जहाजरानी और भारी परिवहन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा भंडारण का एक और महत्त्वपूर्ण माध्यम पंप स्टोरेज परियोजनाएं हैं। अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर पानी को ऊंचे जलाशयों तक पंप किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वही पानी टर्बाइन चलाकर पुनः बिजली उत्पन्न करता है। बैटरी स्टोरेज और पंच स्टोरेज का संयुक्त उपयोग भविष्य की ऐसी ऊर्जा व्यवस्था तैयार करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। हरित ऊर्जा का यह परिवर्तन केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत आज भी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के आयात पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करता है। यदि देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा सूर्य, हवा और जल से प्राप्त कर उसका प्रभावी भंडारण करने में सफल होता है, तो आयातित ईंधनों पर निर्भरता घटेगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और विदेशी मुद्रा की उल्लेखनीय बचत होगी। यही नहीं, वैश्विक ऊर्जा संकटों का प्रभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। इस परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष औद्योगिक विकास और रोजगार भी है। सौर मॉड्यूल, बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रोलाइजर, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। यदि अनुसंधान, नवाचार और घरेलू विनिर्माण को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहा, तो भारत केवल हरित ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी उभर सकता है। निश्चित रूप से चुनौतियां भी हैं। बैटरियों के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता, प्रयुक्त बैटरियों का पुनर्चक्रण, आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क, जल संसाधनों का संतुलित उपयोग तथा पर्याप्त निवेश जैसे विषयों पर समान गंभीरता से कार्य करना होगा। विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जल का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों और पुनर्चक्रित जल के माध्यम से टिकाऊ ढंग से हो, ताकि ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा साथ-साथ आगे बढ़ सकें।

भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के ऐसे चरण में है, जहां सौर ऊर्जा की पहली क्रांति अब ऊर्जा भंडारण की दूसरी क्रांति में परिवर्तित हो रही है। राजस्थान के पूगल सोलर-बैटरी पार्क जैसी परियोजनाएं इस बदलाव की जीवंत मिसाल हैं। वे सिद्ध करती हैं कि भारत की ऊर्जा यात्रा अब केवल दिन में बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिन की धूप को रात की रोशनी में बदलने की क्षमता विकसित कर रही है। हरित ऊर्जा का वास्तविक भविष्य केवल उत्पादन में नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित भंडारण, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन और चौबीसों घंटे उपलब्धता में है। भारत ने इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा दिए हैं। यदि यही गति बनी रही, तो विकसित भारत की ऊर्जा व्यवस्था केवल सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि उन किरणों को संचित करने वाली तकनीकों से संचालित होगी। यही भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का अगला अध्याय है और यही भविष्य की सबसे उज्ज्वल ऊर्जा क्रांति।

मानसून पर निर्भरता छोड़ अपनाएं टिकाऊ जल प्रबंधन तकनीक

'शहरी भारत को पानी का नुकसान घटाने, वर्षा जल संचयन बढ़ाने, शोधित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सुधारने और मौसमी जल-नियोजन को मजबूत बनाने जैसे कदम उठाने चाहिए। इससे शहरों को पानी से तंग ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी स्रोतों से अधिक मात्रा में पानी लाने की जगह पर अपने यहां उपलब्ध पानी के बेहतर ढंग से उपयोग करने में मदद मिलेगी। भारत को अब जल प्रबंधन में 'बारिश-केंद्रित दृष्टिकोण' से हटकर 'लचीलापन-केंद्रित दृष्टिकोण'(रेजिलिएंस-सेंट्रिक अप्रोच) की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। यहां तक कि सामान्य के करीब रहने वाला मानसून भी देश के बड़े हिस्सों में जल संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि सभी समय और जगहों पर एक समान बारिश नहीं होती है।'

मुनीष कुमार उपाध्याय

मानसून ने इस साल एक बार फिर याद दिलाया है कि भारत में पानी की सबसे बड़ी चुनौती कम बारिश नहीं, बल्कि इसकी बढ़ती अनिश्चितता है। कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। खासतौर पर जब अल-नीनो के मजबूत होने की संभावना बनी हुई है, तब सवाल यह नहीं है कि बारिश कितनी कम होगी, बल्कि यह है कि हम इसका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं? एक धीमी शुरूआत के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ी है। लेकिन जल सुरक्षा सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कितनी बारिश हुई है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि बारिश कब और कहां पर हुई है और इसका प्रबंधन कितने प्रभावी ढंग से किया गया है। जून में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई, जिससे कई क्षेत्रों में खरीफ फसलों की बुआई में देरी हुई है। 5 जुलाई 2026 तक, भारत के लगभग 58 प्रतिशत जिलों में कम या बहुत कम बारिश हुई, जो मानसूनी बारिश का असमान वितरण दशार्ता है।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2 जुलाई को भारत के 166 प्रमुख जलाशयों में सिर्फ 47.7 अरब घन मीटर पानी था, जो उनकी कुल जल संग्रहण क्षमता का सिर्फ 26 प्रतिशत है और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 39 प्रतिशत कम है। मानसूनी बारिश की असमानता का सबसे ज्यादा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। ऐसे में, अगर मानसून में जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं जमा होता है तो खरीफ और रबी, दोनों मौसम में फसलों के लिए नहरों से मिलने वाले सिंचाई के पानी की उपलब्धता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इससे खेती की बारिश की अनिश्चितता का सामना करने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। भारत को वर्षा आधारित कृषि को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की लगभग 60 प्रतिशत कृषि भूमि बारिश पर निर्भर है। इसके लिए मिट्टी में नमी को सुरक्षित रखना जरूरी है। सीईईडब्ल्यू के अनुसार, मृदा स्वास्थ्य सुधार, मल्चिंग, जलद्रोणि विकास और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन जैसे उपाय मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे फसलें सूखे का बेहतर सामना कर पाती हैं। साथ ही, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम को इन प्रयासों से जोड़ने और जल-संकट वाले क्षेत्रों में बाजरा, दलहन व तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने से खेती अधिक टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल बन सकती है। सिंचित क्षेत्रों में पानी की हर बूंद का कुशल उपयोग आवश्यक है। सीईईडब्ल्यू और गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी के अध्ययन के अनुसार, सूक्ष्म सिंचाई और विशिष्ट कृषि अपनाने से पानी की खपत 70-80 प्रतिशत तथा ऊर्जा की खपत 25-77 प्रतिशत तक घट सकती है, जबकि फसल उत्पादकता 90 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

इन तकनीकों से भूजल दोहन भी कम होता है। यदि सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग और नीतिगत सुधारों को बढ़ावा दिया जाए, तो 2030 तक सिंचाई जल का लगभग 20 प्रतिशत बचाया जा सकता है। विशेषकर जल-संकट वाले क्षेत्रों में इन उपायों का विस्तार प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा, जल-संरक्षण तकनीकों का लाभ सबसे पहले छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि देश की 85 प्रतिशत से अधिक कृषि जोतें इन्हीं के पास हैं और वे मानसून की अनिश्चितता से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। समय पर मौसम संबंधी सलाह, जलवायु-अनुकूल फसलों की जानकारी, सस्ता ऋण, कृषि विस्तार सेवाएं और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग मिलने से ये किसान नई तकनीकों को तेजी से अपनाते हैं। साथ ही, राज्यों को ऐसी नीतिगत बाधाएं दूर करनी चाहिए, जो छोटे किसानों की सूक्ष्म सिंचाई तक पहुंच में रुकावट बनती हैं। चौथा, गांवों के साथ-साथ शहरों को भी जल संकट के लिए तैयार होना होगा। शहरी भारत को पानी का नुकसान घटाने, वर्षा जल संचयन बढ़ाने, शोधित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सुधारने और मौसमी जल-नियोजन को मजबूत बनाने जैसे कदम उठाने चाहिए। इससे शहरों को पानी से तंग ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी स्रोतों से अधिक मात्रा में पानी लाने की जगह पर अपने यहां उपलब्ध पानी के बेहतर ढंग से उपयोग करने में मदद मिलेगी। भारत को अब जल प्रबंधन में 'बारिश-केंद्रित दृष्टिकोण' से हटकर 'लचीलापन-केंद्रित दृष्टिकोण'(रेजिलिएंस-सेंट्रिक अप्रोच) की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। यहां तक कि सामान्य के करीब रहने वाला मानसून भी देश के बड़े हिस्सों में जल संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि सभी समय और जगहों पर एक समान बारिश नहीं होती है। भारत मानसून को तो नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन इसके लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार जरूर कर सकता है।

समाधि है द्वार

ओशो

चिंतन-मनन

मेरे प्रिय आत्मन, सत्य क्या है? क्या उसकी प्राप्ति अंशतः संभव है? और यदि नहीं, तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है? क्योंकि हरेक मनुष्य संत होना संभव नहीं है, यह पूछा है। पहली बात तो यह, संत होना हरेक मनुष्य की संभावना है। संभावना को कोई वास्तविकता में परिणत न करे, यह दूसरी बात है। यह दूसरी बात है, कि कोई बीज वृक्ष न बन पाए, लेकिन हर बीज वृक्ष होने के लिए अपने अंतस से निर्णीत है। यानी हर बीज की यह संभावना है, यह पोटेंशियलिटी है कि वह वृक्ष बन सकता है। न बने, यह बिलकुल दूसरी बात है। खाद न मिले और भूमि न मिले और पानी न मिले और रोशनी न मिले, तो बीज मर जाए यह हो सकता है, लेकिन बीज की संभावना जरूर थी। संत होना प्रत्येक मनुष्य की संभावना है। इसलिए पहले तो अपने मन से यह ख्याल निकाल दें कि संतत्व कुछ लोगों का विशेष अधिकार है। संतत्व कुछ विशेष लोगों का अधिकार नहीं है। और जिन लोगों ने प्रचलित की है यह धारणा, वह केवल अपने अहंकार के परिपोषण के लिए है। क्योंकि इस बात से अहंकार को परिपोषण मिलता है कि अगर मैं कहूं कि संत होना बड़ा दुरूह है और बहुत थोड़े से लोगों के लिए संभव है। और फिर मैं यह कहूं कि बहुत थोड़े से लोग ही संत हो सकते हैं।

यह कुछ लोगों की अहंता की तृप्ति का मार्ग भर है, अन्यथा संत होना सबकी संभावना है। क्योंकि सत्य को उपलब्ध करने के लिए सबके लिए सुविधा और गुंजाइश है। मैंने कहा कि यह दूसरी बात है कि आप उपलब्ध न हो सके। उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे, आपकी संभावना नहीं जिम्मेवार होगी। हम सारे लोग यहां बैठे हैं। उठकर चलने की हम सबकी शक्ति है, लेकिन हम न चले और बैठे रहें! शक्तियां तो उन्हें सक्रिय करने से ज्ञात होती हैं, जब तक सक्रिय न करें, ज्ञात नहीं होती। अभी आप यहां बैठे हैं, हमको ज्ञात भी नहीं हो सकता कि आप चल सकते हैं। और आप भी अगर अपने भीतर खोजेंगे, तो चलने की शक्ति कहां मिलेगी आपको! एक बैठा हुआ आदमी अपने भीतर खोजे कि मेरे भीतर चलने की शक्ति कहां है? तो उसे कैसे पता चलेगी? उसे पता भी नहीं चलेगी, वह सोचेगा कि चलने की शक्ति कहां है!

आपके पत्र

समय रहते क्यों नहीं संभली केंद्र सरकार?

पेपर लीक मामले में दोषियों को खोजकर सजा देना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दूसरी मांग शिक्षा मंत्री द्वारा इस्तीफा देना है। तीसरी मांग, जिन छात्रों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को मुआवजा देना है। ये मांगें इतनी बड़ी नहीं हैं जितना बड़ा आंदोलन हो गया। इन मांगों को सरकार वार्ता के जरिये सुलझा सकती थी, जिसके लिए अधिकांशतः छात्र आंदोलित थे।

समय रहते बातचीत करके समाधान खोजा जा सकता था सरकार द्वारा। क्योंकि बीच-बीच में बातचीत करने के लिए काकरोच जनता पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। तब बातचीत आखिर क्यों रुकी रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि विद्यार्थियों के आंदोलन का फायदा उठाते हुए इसमें राजनीति प्रवेश कर गई, जिसने छात्र आंदोलन को और भडका दिया।

राकेश शर्मा,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।

प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website :** www.metrorays.in

email : metrorays.ranchi@gmail.com

न्यूज IN ब्रीफ

बानू टोला के चारों सोलर पावर प्लांट मिले चालू, 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग

साहिबगंज/उधवा : प्रखंड की दक्षिण पलाशगाछी पंचायत स्थित बानू टोला में स्थापित सोलर पावर प्लांटों एवं विद्युत वितरण प्रणाली का सोमवार को विद्युत विभाग की टीम ने भौतिक सत्यापन किया। यह जांच 28 जून को उपायुक्त के गोलढाब चुआर दौरे के दौरान ग्रामीणों द्वारा 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग उठाए जाने के बाद कराई गई। राजमहल विद्युत प्रमंडल के कनिष्ठ अभियंता चंदन कुमार अपनी टीम के साथ बानू टोला पहुंचे और क्षेत्र में स्थापित सभी चार सोलर पावर प्लांटों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान बानू टोला1 ,100 किलोवाट, 150 घर), बानू टोला-02 (100 किलोवाट, 175 घर), बानू टोला (अंश असराउल टोला-03) (100 किलोवाट, 160 घर) और बानू टोला अंश हाजी टोला 04(75 किलोवाट, 100 घर) का भौतिक सत्यापन किया गया।निरीक्षण में सभी सोलर पावर प्लांट, सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी बैंक तथा विद्युत वितरण प्रणाली सामान्य एवं कार्यशील अवस्था में पाए गए। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने विभागीय टीम को बताया कि सोलर प्लांट से बिजली की आपूर्ति तो हो रही है। लेकिन प्रतिदिन केवल 12 से 15 घंटे ही बिजली मिल पाती है। ग्रामीणों ने कहा कि सीमित अवधि तक बिजली मिलने से पेयजल के लिए मोटर चलाने, फ्रिज, पंखा, बच्चों की पढ़ाई तथा अन्य घरेलू एवं कृषि कार्यों में परेशानी होती है। उन्होंने विभाग से मांग की कि सोलर पावर प्लांट की क्षमता, बैटरी बैकअप एवं अन्य तकनीकी संसाधनों का विस्तार कर क्षेत्र में 24 घंटे नियमित एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि विभाग उनकी मांग पर सकारात्मक पहल करते हुए सोलर प्रणाली को और सुदृढ़ बनाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को चौबीसों घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल सके।

कुल्हाड़ी से किया वार रासो मुनी मरांडी की हुई घटना स्थल पर मौत

साहिबगंज/तीनपहाड़ : थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में गुरुवार की शाम को अपने चाची को खुद का भतीजे ने कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दिया गया।मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव निवासी रासो मुनी मुर्मू अपने घर के आंगन में खाना खा रही थी तभी उसके पति स्व होपा मरांडी के भतीजा धुनु मरांडी कुल्हाड़ी से सिर पर और कान के पास वार कर दिया जिससे रासो मुनी मरांडी का घटना स्थल पर ही मौत हों गया।वही इसकी सूचना तीनपहाड़ थाना को मिलते ही तीनपहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार पांडे एस आई शाहिद अहमद खान,एएसआई उमेश उपाध्याय बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर शव को अपने कब्जे में लिया।वही इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दिया गया।सूचना पर राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर राजीव रंजन भी घटना स्थल पर पहुच कर मामले की जाच किया और शव को पोस्टमार्टम के लिये अनुमंडल असपताल राजमहल भेज दिया गया ।
ग्रामीणों के अनुसार मृतक और उसके पति का भतीजा धुनु मरांडी से जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था।वही मृतक रासो मुनी मुर्मू अपने देख भाल के लिये अपने नाती दिलीप जर्मन हेम्ब्रम को साथ रखती थीं जो धुनु मरांडी को रास नहींआया और वह कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गया।वही इस मामले में पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिये राजमहल अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है मामले की जांच किया जा रहा है।

राहुल कुमार जयसवाल के जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई

साहिबगंज : जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला अंबाडीहा निवासी महिला राखी देवी पति राहुल कुमार जयसवाल ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देते हुए अपने पति राहुल कुमार जयसवाल के जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।जहां दिए गए आवेदन पत्र में पीड़िता महिला ने बताया कि उसके पति राहुल कुमार जयसवाल ने अंजली देवी नामक महिला से पहले शादी की थी जहां उसे कुछ समय के बाद छोड़ दिया था।उधर पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उससे शादी कर लिया और उसके साथ वो खुशी खुशी रह रही है।वही अब उसके पति की पहली पत्नी अंजली देवी,उसकी मां अन्य बदमाशो को अपने साथ लेकर बीते दिनों 22 जुलाई 2026 को उसके घर पर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जिसके कारण पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को विवश है।जहां पीड़िता महिला ने पुलिस अधीक्षक से अपने पति समेत पूरे परिवार के जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है।

विभावि योग केंद्र मे डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मे नामांकन प्रारंभ

हजारीबाग : विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के योग केंद्र में पीजी डिप्लोमा इन योग सत्र 2026-27 एवं पीजी इन योग एंड नेचरोपैथी सत्र 2026-28 पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट सूची एवं काउंसिलिंग के आधार पर किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए केंद्र के निदेशक डॉ राजकुमार चौबे ने बताया कि नामांकन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोनों ही पाठ्यक्रम में समान है। बताया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक प्रतिष्ठा मेजर के विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक से जनरल कोर्स पास करने वाले अभ्यर्थी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 5 अगस्त 2026 तक चांसलर पोर्टल पर निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में नामांकन से संबंधित लिंक विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों को 10वीं से स्नातक तक के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, आवेदन प्रपत्र की प्रति एवं पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करना होगा ।

किसानों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ करें कार्य : उपायुक्त

उपायुक्त ने कृषि उद्यान सहकारिता एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

खरीफ योजना केसीसी मधुमक्खी पालन एवं पशुधन विकास योजनाओं की प्रगति की उपायुक्त ने की समीक्षा

संवाददाता
साहिबगंज : उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में कृषि, आत्मा, सहकारिता, उद्यान, जिला पशुपालन कार्यालय एवं जिला गव्य विकास कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सघन निरीक्षण अभियान निरंतर जारी है। अब तक 21 उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया है तथा अनियमितता पाए जाने पर 6 प्रतिष्ठानों को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया है। किसानों को संतुलित एवं अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में वर्षापात की स्थिति सामान्य से बेहतर है। जुलाई माह में सामान्य वर्षापात 289.90 मि.मी. के विरुद्ध अब तक 291.77 मि.मी. वर्षापात दर्ज किया गया है। जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा हुई है, वहां कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।खरीफ वर्ष 2026-27 के अंतर्गत बीज विनिमय एवं वितरण योजना के तहत प्रमाणित धान बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक धान की उन्नत किस्म एमटीयू-7029 के 530 क्विंटल बीज की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध 498 क्विंटल बीज का वितरण 585 किसानों के बीच किया जा चुका है।इसके अतिरिक्त बिरसा फसल विस्तार योजना के अंतर्गत मूंग के 100 क्विंटल, मक्का के 6 क्विंटल तथा रागी के 3.2 क्विंटल बीज प्राप्त हुए हैं, जिनका वितरण पात्र किसानों के बीच निरंतर किया जा रहा है। बताया गया कि जिले में बीज एवं अन्य कृषि उपादानों के वितरण हेतु ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से किसानों का निबंधन किया जा रहा है। अब तक 67,430 किसानों का निबंधन पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष किसानों का निबंधन भी निरंतर जारी है।कृषि ऋण माफी योजना एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के अंतर्गत अब तक 1,737 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए हैं, जिनमें 1,732 आवेदन स्वीकृत कर किसानों को कुल 1,248.74 लाख रुपये का कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है।
प्रखंडवार ई-केवाईसी प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 20,094 ऋणी कृषकों में से 13,760 का ऑनलाइन ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है, जबकि 2,663 वास्तविक लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिया।उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत संचालित मधुमक्खी पालन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि योजना के तहत 480 मधुमक्खी बक्से, 480 मधुमक्खी छत्ते 8 फ्रेम 24 मधु प्रोसेसिंग इकाइयों 30 किलोग्राम क्षमता तथा 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।बैठक में यह भी बताया गया कि लाभुकों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अंतर्गत 100 एमटी एवं 500 एमटी क्षमता वाले गोदामों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर शीघ्र हैंडओवर की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। साथ ही 100 एमटी क्षमता के 06 गोदाम, जो भौतिक रूप से पूर्ण है, को संबंधित लैंम्प्स को हस्तगत कराया जाय।पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 1,197 लाभुकों का चयन कर डीबीटी स्वीकृत किया गया, जिनमें से अब तक 780 लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान में योजना की उपलब्धि 65.16 प्रतिशत है। जबकि बकरा विकास सूकर विकास, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट पालन ब्रायलर कुक्कुट पालन तथा बतख चूजा वितरण योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष चयनित लाभुकों को भी निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रगति पर है।बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का, जिला सहकारिता पदाधिकारी महादेव मुर्मू, जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन, जिला विज्ञान एवं मूल्यांकन पदाधिकारी अरुण कुमार भोक्ता, जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज और नशामुक्ति कानूनी जागरूकता विषय पर निबंध

संवाददाता
साहिबगंज : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निदेशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में संचालित 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज कस्तूरबा विद्यालय, साहिबगंज में छात्राओं के बीच ₹नशामुक्ति₹ विषय पर निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशामुक्त समाज के निर्माण, कानूनी जागरूकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशामुक्ति, बाल अधिकार एवं मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर अपने विचारों एवं रचनात्मक प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 9 की छात्रा सपना कुमारी ने प्रथम, सोनम कुमारी ने द्वितीय तथा रुचि कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में अर्चना, नन्दिनी एवं काजल कुमारी ने संयुक्त रूप से प्रथम, डॉली कुमारी, अंजली खातून एवं अनुश्का कुमारी ने संयुक्त द्वितीय तथा प्रगति कुमारी, सुनीता कुमारी एवं स्वर्णलता सोरेन ने संयुक्त तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया। जबकि छात्राओं द्वारा मानव तस्करी जैसे गंभीर सामाजिक अपराध पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। जिसने उपस्थित सभी लोगों को जागरूक एवं भावुक किया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी चीफ एलएडीसी श्रीमती कामिनी शर्मा ने छात्राओं को पोक्सो एक्ट गुड टच हुआ बैड टच और बाल सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वहीं डिप्टी चीफ एलएडीसी श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बाल श्रम एवं मानव तस्करी की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। असिस्टेंट एलएडीआरओ श्री रतन कुमार ने छात्राओं को शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं नालसा हेल्पलाइन 15100 की उपयोगिता एवं सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया।कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम, विद्यालय परिवार एवं छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही। उपस्थित सभी अधिकारियों ने छात्राओं को नशामुक्त जीवन, शिक्षा, कानूनी अधिकारों तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।

लाठीचार्ज में विरोध में झामुमो ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला

संवाददाता
साहिबगंज : जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों एवं नौजवानों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 व सीबीएसई मार्किंग में हुई गड़बड़ी को लेकर विरोध जता रहे आंदोलनरत छात्र एवं छत्राओं पर हुए लाठीचार्ज व बर्बरतापूर्ण बर्ताव के विरोध में झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण सिंह जी के नेतृत्व में जिले के में पैदल आक्रोश मार्च करते हुए जिले के स्टेशन चौक में केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया।मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा छात्र एवं छत्राओं हुए लाठी चार्ज की हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है। जब छात्र व नौजवानों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया जा रहा था,तो केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से उन्हें डरा-धमकाकर मार-पीट कर छात्रों के आंदोलन को समाप्त करना चाहती है।कहा कि भाजपा ने केंद्र की सत्ता में बैठने के लिए हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था,लेकिन नई नौकरी देने के बजाय हर बार पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। अभी हाल ही में नीट परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया,यह पूरी तरह से छात्रों के साथ अन्याय है।छात्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हर बार परीक्षा की तैयारी करते है लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार छात्रों के परिश्रम पर पानी फेर देती है।वही जिला उपाध्यक्ष सह केंद्रीय समिति सदस्य संजीव शामू हेंब्रम व संजय मिश्रा मो मारुफ उर्फ गुड्डू ने अपने अपने संबोधन में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार छात्रों का हित नही चाहती है।हर बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है इसे हमारी पार्टी कतई बर्दाश्त नही करेगी।छात्रों व नौजवानों पर केंद्र सरकार के निर्देश पर हुए लाठीचार्ज की हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है।हमारी पार्टी छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है।विरोध प्रदर्शन में जिला युवा मोर्चा सचिव मो मारुफ उर्फ गुड्डू, केंद्रीय समिति सदस्य संजय मिश्रा उर्फ बबलू मिश्रा,केंद्रीय समिति सदस्य मुजीबुर रहमान,अखलाकुर रहमान, नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान,जिला संगठन सचिव छवि हेंब्रम,काजू मल्लिक,जिला कार्यकारिणी सदस्य अब्दुल बारीक शेख,जंग बहादुर सिंह, जलेबी सिंह,जेम्स किस्कू,नसीम अंसारी,जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मो अली,देव सोरेन,मो एजाज अंसारी सहित अन्य उपस्थित थे।

योग केंद्र में पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह 30 को

हजारीबाग : विभावि के योग केंद्र में 30 जुलाई को पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा।यह जानकारी योग केंद्र के निदेशक डॉ राजकुमार चौबे ने दी। बताया कि इस मिलन समारोह में योग केंद्र से शिक्षा प्राप्त कर चुके सभी पूर्व छात्र आमंत्रित हैं। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक योगाभ्यास, अनुभव साझा करना और योग के क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। साथ ही केंद्र के भावी कार्यक्रमों और विस्तार को लेकर पूर्व छात्रों से सुझाव भी लिए जाएंगे।

विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण : बरकतुल्लाह

संवाददाता
साहिबगंज : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमिटी ने गुरुवार को स्टेशन चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे,प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं छात्रों के साथ हुए अन्याय और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों एवं नेताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान ने की।कार्यक्रम के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।इसके पूर्व जिला अध्यक्ष ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस सांसदों और नेताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया। वह लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मयार्दाओं के अनुरूप नहीं है।उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है।लेकिन उनकी न्यायपूर्ण मांगों को सुनने के बजाय उन पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है।कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहेगी।प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमिटी के सदस्य अनुकूल मिश्रा ने कहा कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है।उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।जिला उपाध्यक्ष मो. कलीमुद्दीन ने कहा कि आज का यह धरना जनता और छात्रों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है।कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती रही है और आगे भी छात्रों की हर न्यायपूर्ण मांग के समर्थन में मजबूती से खड़ी रहेगी। सरकार को दमन का रास्ता छोड़कर युवाओं की आवाज सुननी चाहिए।जिला कांग्रेस कमिटी के महासचिव सरफराज आलम ने कहा कि यह आंदोलन केवल छात्रों का नहीं,बल्कि देश के हर उस परिवार की लड़ाई है जिसके बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। छात्रों के साथ अन्याय,लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर दमन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।कांग्रेस पार्टी छात्रों, युवाओं और संविधान की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी।इधर सौंपे गए ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे,परीक्षा में हुई अनियमितताओं एवं व्यवस्थागत विफलताओं पर कठोर कार्रवाई, छात्रों एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर और आपराधिक मामलों की वापसी तथा छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई।मौके पर अनुकूल मिश्रा,हीरालाल साह,मो कलीमुद्दीन,बासुकीनाथ यादव,उमेश पांडे,मो मुरसलीन खान,सुनील कुमार पासवान,अनिल पांडे,कज्जाफी बिन मुर्शाद,सद्दाम हुसैन,शौकत अली, दुर्गा प्रसाद गुप्ता,मंगल पासवान, मृत्युंजय यादव,मो गफ्फार,अरविंद कुमार यादव,आकाश,मो रिजवान, मो रउफ, मो सिफरोज अख्तर,बीबी नूरजहां, तारा खातून,सतीश कुमार पासवान,मो मेराजुद्दीन,मो मजहर खान,जमुना दास,मो रियाज,विजय वर्मा,अली कुरैशी,सब्दुल अंसारी, कौसर आलम,देवराज सिंह,ललन कुमार,रवीना बेगम,बीबी शहनाज, मोफिज आलम,परवेज आलम,मो नुरशेद,संटू यादव,गणेश पासवान, रामप्रवेश राय,मो अलीरजा,करीम नवाब,तनवीर अहमद,मुनमुन अग्रवाल, आरिफ अहमद एवं दर्जनों कांग्रेसी मौजूद थे।

फिल्म समीक्षा

पुराने बॉलीवुड रोमांस की ताजा झलक है दुल्हनिया ले आएगी खुशाली कुमार की परफॉर्मेंस बनी फिल्म की जान

आज के दौर में जहां ज्यादातर फिल्में बड़े संदेश, एक्शन या चौंकाने वाले ट्विस्ट के सहारे दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, वहीं 'दुल्हनिया ले आएगी' एक हल्की-फुल्की, साफ-सुथरी फैमिली एंटरटेनर के रूप में सामने आती है। यह फिल्म प्यार, रिश्तों, परिवार और शादी से जुड़ी भावनाओं को मनोरंजन के साथ बड़े सहज अंदाज में पेश करती है। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और इमोशन का संतुलन ऐसा है जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखता है। अगर आप बिना किसी भारी-भरकम ड्रामे के परिवार के साथ एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है।

कहानी: फिल्म की कहानी नव्या (खुशाली कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। कई कोशिशों के बाद जब आखिरकार उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ती है, तो उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आते हैं जो कहानी को दिलचस्प बना देते हैं। कई नए किरदारों की एंट्री, रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां, मजेदार घटनाएं और भावुक पल कहानी को लगातार आगे बढ़ाते हैं। फिल्म आखिर तक दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखती है कि आखिर नव्या का जीवनसाथी कौन बनेगा। हालांकि दूसरे हाफ में कहानी कुछ जगह धीमी पड़ती है और कुछ ट्विस्ट पहले से अनुमानित लगते हैं, लेकिन मनोरंजन का सिलसिला बना रहता है।

एक्टिंग: फिल्म की सबसे बड़ी ताकत खुशाली कुमार हैं। उन्होंने नव्या के किरदार को आत्मविश्वास, सहजता और भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। इमोशनल दृश्यों में उनकी परफॉर्मेंस प्रभाव छोड़ती है, जबकि रोमांटिक और कॉमिक सीन्स में भी वह पूरी तरह सहज नजर आती हैं। यह फिल्म उनके अभिनय करियर में एक मजबूत पड़ाव साबित हो सकती है।

वहीं महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा जैसे अनुभवी कलाकार अपने दमदार अभिनय से कहानी को मजबूती देते हैं। ओमकार कपूर अपने किरदार में फिट बैठते हैं और स्नेहिल दीक्षित मेहरा अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से कई दृश्यों को मनोरंजक बना देती हैं। पूरी स्टारकास्ट के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फिल्म कहीं भी बिखरी हुई महसूस नहीं होती।

डायरेक्शन: निर्देशक आकाशादित्य लामा ने फिल्म को जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक बनाने की बजाय सरल और मनोरंजक अंदाज में पेश किया है। उन्होंने कहानी की पारिवारिक भावनाओं और हल्के-फुल्के हास्य के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखा है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भावनात्मक दृश्यों को और असरदार बनाते हैं, जबकि शादी से जुड़े सीक्वेंस रंगीन और आकर्षक नजर आते हैं। हालांकि दूसरे हाफ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है और कुछ घटनाएं अनुमानित लगती हैं, लेकिन निर्देशन इतना संतुलित है कि फिल्म अपनी पकड़ नहीं खोती।

फाइनल वर्डिक्ट: 'दुल्हनिया ले आएगी' एक ऐसी फैमिली एंटरटेनर है जो बिना किसी बड़े दावे के दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रहती है। रोमांस, कॉमेडी, इमोशन और पारिवारिक रिश्तों का खूबसूरत मेल इसे एक साफ-सुथरी और मनोरंजक फिल्म बनाता है। खुशाली कुमार का प्रभावशाली अभिनय, मजबूत सहायक कलाकार और सरल निर्देशन फिल्म की सबसे बड़ी खूबियां हैं। अगर आप पूरे परिवार के साथ हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो 'दुल्हनिया ले आएगी' एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है।

रामायण का इंतजार बढ़ा, मेकर्स ने लॉन्च टाला

रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायणः पार्ट वन-द इंट्रोडक्शन' का ट्रेलर आज (24 जुलाई 2026) सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शानदार लॉन्च के बाद रिलीज होने वाला था। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि टीम उनके लिए क्या लेकर आई है। हालांकि, रिलीज से कुछ घंटे पहले ही मेकर्स ने इसे टालने का फैसला किया। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ??ने एक ऑफिशियल बयान में इस अपडेट की पुष्टि की और देरी की वजह भी बताई। 'रामायण' टीम ने फिल्म की ग्लोबल रिलीज के लिए सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप की है और इसी सहयोग के चलते उन्होंने घोषणा की है कि ट्रेलर अब बाद की तारीख में लॉन्च किया जाएगा।

रामायण ट्रेलर लॉन्च अपडेटः 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ?ने जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारी 'रामायण' के लिए बहुत खास पल है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ हमारी पार्टनरशिप से 'रामायण' को दुनिया तक पहुंचाने का मेरा सपना अब सच हो रहा है। इसी वजह से, हम अपना ट्रेलर बाद की तारीख में ग्लोबली लॉन्च करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सिनेमा के 100 से ज्यादा सालों के इतिहास में यह गर्व का पल होगा जब 'रामायण' को किसी बड़ी ग्लोबल हॉलीवुड फि ल्म की तरह पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा।

नमित मल्होत्रा की महागाथाः 'रामायणम्' का 24 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होगा ट्रेलर

नमित मल्होत्रा की महागाथा 'रामायणम्' का 24 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होगा ट्रेलर

उन्होंने आगे कहा कि यह खास है क्योंकि इससे दुनियाभर के लोगों के लिए नए गर्व और उत्साह के साथ हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों की समृद्धि को जानने का दरवाजा खुलता है। मल्होत्रा ??ने इस अहम पड़ाव को मुमकिन बनाने में मदद करने के लिए 'रामायण' के सभी फैंस और चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। देशभर में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर इशारों-इशारों में बात करते हुए, उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि देश के युवा ही इसका भविष्य हैं और सभी से उस भविष्य की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आग्रह किया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में देरी पर अपनी निराशा जाहिर की।

रामायण ट्रेलर लॉन्चः कई लोगों ने कहा कि वो फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए पूरी रात जागे थे और मार्केटिंग टीम से सवाल किया कि उन्होंने हाइप क्यों खत्म कर दी। हालांकि, दूसरों ने कहा कि उन्हें अभी भी मेकर्स के विजन पर भरोसा है और वे नई रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'रामायण' का ट्रेलर हाल ही में दिल्ली और मुंबई में प्राइवेट स्क्रीनिंग में दिखाया गया था। आज, इसे सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में दिखाया जाना है। रणबीर, यश और अन्य लोग इस शानदार इवेंट के लिए अमेरिका रवाना हो चुके हैं।

राजकुमार हिरानी की 'प्रीतम एंड पेड्रो' पहुंची हजारों स्कूलों तक, बच्चों को सिखाएगी साइबर सुरक्षा का पाठ

आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे हर दिन औसतन कई घंटे ऑनलाइन बिताते हैं, ऐसे में साइबर सुरक्षा एक बड़ी जरूरत बन गई है। यह पहल बच्चों को साइबर अपराध, डिजिटल प्राइवेसी और इंटरनेट के सुरक्षित व जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सीरीज आसान और मनोरंजक कहानी के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन दुनिया की चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के तरीके सिखाती है।

साइबर बुलिंग और ऑनलाइन खतरों के प्रति जागरूकता पर जोर : आज के समय में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक गंभीर विषय बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में बच्चे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण जैसी समस्याओं का सामना कर चुके हैं। ह्यढ१३ें & ढीरि्ङ्क्ल बच्चों को सिर्फ साइबर सुरक्षा की जानकारी ही नहीं देती, बल्कि उन्हें ऑनलाइन शिष्टाचार, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और साइबर बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित करती है। सीरीज का उद्देश्य बच्चों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना है।

स्कूलों और समुदायों तक पहुंच रहा है जागरूकता अभियान : सीरीज के संदेश को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक बड़े जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई है।

अभियान के दौरान स्कूलों में विशेष स्क्रीनिंग, कक्षा चर्चाएं, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि बच्चे और परिवार डिजिटल दुनिया को सुरक्षित तरीके से समझ सकें।

कहानी के जरिए डिजिटल सुरक्षा का संदेश : 'प्रीतम एंड पेड्रो'कहानी कहने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रही है। मनोरंजन के साथ जरूरी जानकारी देने वाली यह पहल बच्चों को सुरक्षित, समझदार और जिम्मेदार इंटरनेट यूजर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

समिक्षा और शैल ओसवाल की निजी जिंदगी से प्रेरित है मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी

आगामी फिल्म मैक्स, मिन एंड म्याऊजाकी की निमार्ता समिक्षा ओसवाल ने खुलासा किया है कि फिल्म की भावनात्मक कहानी उनकी और सह-निमार्ता शैल ओसवाल की वास्तविक जिंदगी से प्रेरित है। समिक्षा ओसवाल ने कहा कि उन्हें जानवरों से एलर्जी थी, जबकि शैल ओसवाल बड़े पशु प्रेमी हैं और उनके फार्महाउस पर बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों की देखभाल की जाती है।

उन्होंने बताया कि शैल के पालतू कुत्तों को अपनाने और उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की प्रक्रिया ने उन्हें रिश्तों में किए जाने वाले छोटे-छोटे समझौतों का महत्व समझाया, जो इस फिल्म की प्रेरणा बना। उन्होंने कहा कि यह फिल्म केवल एक बिल्ली को केंद्र में रखकर बनाई गई कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, बिछड़ने, रिश्तों के घाव भरने और परिवार के मजबूत संबंधों की भावनात्मक यात्रा भी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं और यह फिल्म उन्हें रिश्तों को महसूस करने तथा संजोने का संदेश देती है। समिक्षा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती बिल्ली को मुख्य किरदार के रूप में फिल्माना था।

उन्होंने कहा कि बिल्ली अक्सर सेट पर लाइटों के बीच दौड़ जाती थी या सो जाती थी, जिसके कारण पूरी टीम को धैर्य के साथ उसका इंतजार करना पड़ता था और शूटिंग सामान्य फिल्मों की तुलना में अधिक समय तक चली। पद्मकुमार नरसिम्हामूर्ति द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में मेधा शंकर, सिद्धार्थ मेनन, आदिल हुसैन, मंदिरा बेदी, नासर, नफीसा अली और विधात्री बांदी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। एसएसओ प्रोडक्शंस के बैनर तले शैल ओसवाल और समिक्षा ओसवाल द्वारा निर्मित यह फिल्म 24 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

5 अगस्त से स्टार प्लस पर ये फितूर तेरा

स्टार प्लस के नए शो ये फितूर तेरा की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया गया है। शो की कहानी इलाहाबाद की रहने वाली सौम्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हमेशा इस चिंता में रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यही डर उसे अपनी बात कहने से रोकता है। को-एड कॉलेज में दाखिले के बाद उसे नए माहौल, नए लोगों और नए रिश्तों का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जीत से होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती अपने डर और असुरक्षाओं से लड़ना है।

सौम्या का किरदार निभा रहीं देबचंद्रिमा सिंघा रॉय ने कहा कि शुरूआत से ही वह इस किरदार से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती थीं। उन्होंने कहा कि सौम्या ऐसी लडकी है जो लोगों से जुड़ना चाहती है, लेकिन उसके अपने डर उसे रोक लेते हैं। अक्सर लोग किसी शांत इंसान को देखकर उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, जबकि उसके मन में चल रही भावनाओं और संघर्षों को नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा कि सौम्या की हर झिझक और खामोशी के पीछे एक वजह है और यही बात इस किरदार को बेहद वास्तविक बनाती है। देबचंद्रिमा को विश्वास है कि कई लड़कियां खुद को इस किरदार में देख पाएंगी। देबचंद्रिमा सिंघा रॉय और ईशान धवन अभिनीत यह शो 05 अगस्त से हर रात 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। दर्शक इसे जियोहॉटस्टार पर भी देख सकेंगे।

भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार डोप टेस्ट में फेल

एजेंसी/ ग्लासगो: कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से ठीक पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। वह 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल के दावेदार थे। उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि अरुण से पदक की उम्मीद थी, लेकिन इतने कम समय में उनका विकल्प नहीं चुना जा सकता।

पंच से पहले ही भारत का पदक पक्का, लवलीना को बाई मिली, बिना लड़े सेमीफाइनल में पहुंचीं

एजेंसी/ ग्लासगो: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत ने अपना पहला पदक पक्का कर लिया। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बाई मिली है। इसके माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में पहुंचते हुए उन्होंने अपना पदक सुनिश्चित कर लिया। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों बॉक्सर्स को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है।

इसका मतलब है कि ग्लासगो में अपना पहला मुकाबला खेलने से पहले ही लवलीना का कांस्य पदक पक्का हो गया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन बाय मिलने के बाद महिलाओं के 75 किग्रा कैटेगरी के सेमीफाइनल में सीधे पहुंची। ड्रॉ में सिर्फ पांच एथलीट थे, इसलिए लवलीना समेत तीन खिलाड़ी सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि बाकी दो खिलाड़ियों को एकमात्र क्वार्टरफाइनल मैच खेलना था।

दो कॉमनवेल्थ में रह चुकी हैं खाली हाथ: लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल में ताफाकी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी, जहां गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाने का मौका होगा। जीत उन्हें फाइनल में पहुंचाएगी और कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करेगी, जबकि हारने पर भी वह ब्रॉन्ज के साथ लौटेंगी। यह कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका पहला पोडियम फिनिश होगा। लवलीना गोल्ड कोस्ट 2018 में क्वार्टरफाइनल में चैंपियन बनीं सैंडी रयान से हार गई थीं और बर्मिंघम 2022 में अपना पहला ही मुकाबला हार गई थीं। उन्होंने पिछले दोनों इवेंट्स में 69 किग्रा कैटेगरी में हिस्सा लिया था।

लॉन बॉल्स में भारत का विजयी आगाज, कॉमनवेल्थ गेम्स की महिला पेयर्स ने बॉल्स स्पर्धा में हराया माल्टा

एजेंसी/ ग्लासगो: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने गुरुवार को शानदार आगाज किया। महिला पेयर्स बॉल्स स्पर्धा में भारत ने माल्टा को रोमांचक टाई-ब्रेक में हराकर जीत से अभियान शुरू किया। ग्रुप बी के इस मुकाबले में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी उतरी। रूपा ने लीड और पिंकी ने स्किप की भूमिका निभाई। पहला सेट भारत ने 7-1 से आसानी से जीत लिया। दूसरे सेट में माल्टा की रेबेका लूसी रिक्सन और कोनी ले रिक्सन ने वापसी की और 4-3 से सेट अपने नाम कर लिया। मैच 1-1 से बराबर होने पर फैसला टाई-ब्रेक से हुआ। टाई-ब्रेक में भारतीय जोड़ी एक समय पीछे चल रही थी। आखिरी गेंद पर पिंकी ने गजब का शॉट खेला और भारत को निर्णायक बढ़त दिला दी। इसी के साथ भारत ने मैच जीत लिया।

अब शुक्रवार को ग्रुप बी के दूसरे मैच में भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। टिर्की और पिंकी दोनों 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली महिला फोर्स टीम का हिस्सा थीं। हालांकि इस बार ग्लास्गो में पुरुष और महिला फोर्स स्पर्धा हटा दी गई है। अब सिर्फ सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले हो रहे हैं। भारत ने बर्मिंघम में पुरुष फोर्स में सिल्वर भी जीता था।

न्यूज ब्रीफ

अधर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर छात्रों से माफी मांगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने, छात्रों से माफी मांगने तथा छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। श्री खडगे तथा श्री गांधी ने श्री मोदी के वीडियो के जरिए पेपरलीक को लेकर दिए गए बयान पर शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब संसद चल रही होती है, तो प्रधानमंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देर रात संसद के बाहर एकतरफा ह्यमन की बातह्न नहीं करनी चाहिए। उन्होंने श्री मोदी से संसद में आने से पहले श्री प्रधान को बर्खास्त करने, छात्रों से माफी मांगने तथा छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठी-डंडों और पैलेट गन का इस्तेमाल कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। श्री खडगे ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से इस दिशा में यह सारे कदम उठाए जाने के बाद ही कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। श्री गांधी ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस दयनीय वीडियो से उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान मत कीजिए। उन्होंने आग्रह करते हुए सरकार से कहा कि श्री प्रधान को बर्खास्त किया जाए, छात्रों की पिटाई करने वालों को दंडित किया जाए और छात्रों से माफी मांगी जाए।

बोह में उजड़े 38 परिवार, 23 मकान तबाह, दो विशाल चट्टानों के खतरे में 12 परिवार, राहत एवं बचाव में जुटी सेना

धर्मशाला: शाहपुर उपमंडल की बोह घाटी में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर अब भी दहला रहा है। 38 परिवारों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। 23 मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जबकि 12 अन्य परिवारों की सांसें पहाड़ी पर अटकी दो विशाल चट्टानों के साये में अटकी हुई हैं। लगातार खिसक रही मिट्टी के कारण ये चट्टानें कभी भी नीचे आ सकती हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने मौसम साफ होने तक इन्हें हटाने का जोखिम नहीं लेने का फैसला किया है। प्रशासन ने खतरे वाले इलाकों को खाली करवाकर प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए वैकल्पिक भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दुर्गम इलाकों में राहत कार्य तेज करने के लिए भारतीय सेना को भी मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना के जवान फंसे लोगों और उनके सामान को सुरक्षित निकालने के साथ राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। घडूह गांव तक मार्ग बहाल होते ही वहां विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से विधायक केवल सिंह पठानिया और जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट ली है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से फोन पर बात कर हरसंभव सहायता का भरोसा दिया और जल्द स्वयं बोह घाटी का दौरा कर नुकसान का आकलन करने की बात कही। उधर, चंबा जिला के चुराह उपमंडल में गुरुवार को बैरागढ़-साचपास-किलाड़ मार्ग पर बादल फटने से नालों में उफान आ गया है और इस मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसके चलते पांगी क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। प्रदेश में बारिश का असर व्यापक है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार 260 सडकें प्रभावित हुई थीं, जिनमें से 147 बहाल कर दी गई हैं। कांगड़ा जोन में बंद हुई 68 में से 50 सडकें यातायात के लिए खोल दी गई हैं, जबकि शेष मार्गों को बहाल करने का काम जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक कांगड़ा समेत मध्य पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तोड़ा अनशन

नई दिल्ली: पेपर लीक के मुद्दे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को अपना अनशन तोड़ दिया। वह गत 28 जून से अनशन पर थे। श्री वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा जेपी नड्डा की मौजूदगी में गुरुग्राम के मेदान्ता अस्पताल में अपना अनशन तोड़ा। श्री वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर 28 जून से अनशन शुरू किया था। पुलिस ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुये शनिवार को उन्हें जंतर-मंतर से जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करया था उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के दखल और श्री वांगुचुक की इच्छा के अनुरूप उन्हें मेंदान्ता अस्पताल में भर्ती किया गया था।

श्री नड्डा तथा श्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को अस्पताल जाकर श्री वांगचुक से मुलाकात की थी और उनसे अपना अनशन समाप्त करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक से जुड़े मामलों में उचित कदम उठा रही है। इसके बाद श्री वांगचुक ने दोनो मंत्रियों के नाम एक खुला पत्र लिखा था और उनसे मिले आश्वासन का उल्लेख करते हुए कहा था कि यदि सरकार उन्हें यह आश्वासन भी दे की प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेगी तो वह अपना अनशन तोड़ देंगे। तुरंत यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि सरकार की ओर से श्री वांगचुक को क्या आश्वासन दिये गये है।

फ्लिपकार्ट से मंगाया 1.11 लाख का आईफोन बॉक्स खुला तो निकला दाढ़ी का तेल, कंज्यूमर फोरम ने लगाया तगड़ा जुर्माना

,5

मुंबईः ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अगर आपके मंगाए गए कीमती सामान की जगह कोई मामूली चीज निकल आए, तो यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से 1 लाख रुपये से ज्यादा का आईफोन 14 प्रो ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉक्स खोलने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पार्सल के अंदर चमचमाते स्मार्टफोन की बजाय दाढ़ी बढ़ाने का तेल (बियर्ड ऑयल) और कागज की पैकिंग सामग्री भरी हुई थी। महीनों तक चक्कर काटने के बावजूद जब कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की, तो पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब मुंबई (उपनगरीय) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट और उसके सेलर को कड़ी फटकार लगाते हुए ग्राहक को 1.81 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा चुकाने का ऐतिहासिक आदेश दिया है।

सिर्फ माल बेचकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती कंपनी : उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठ ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ग्राहक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी कीमत चुकाकर यह ऑर्डर दिया था। ऐसे में यह फ्लिपकार्ट का मुख्य दायित्व था कि ग्राहक तक सही और सुरक्षित सामान पहुंचे। आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवल बिक्री कराके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। जब ग्राहक ने तुरंत गलत सामान मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी, तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करना और समस्या का समाधान करना कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी बनती है।

बार- बार शिकायत बंद करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार करार : आयोग ने फ्लिपकार्ट और उसके सेलर इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड दोनों को सेवा में भारी लापरवाही और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस (अनुचित व्यापारिक व्यवहार) का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित ग्राहक द्वारा सबूत देने के बावजूद मामले की ठीक से जांच न करना, गलत पार्सल वापस न लेना और न ही रिफंड देना उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। इसके विपरीत, कंपनी द्वारा बिना कोई ठोस समाधान दिए बार-बार शिकायत को सॉल्व बताकर बंद कर देना यह दशार्ता है कि ग्राहकों के हितों के प्रति भारी लापरवाही बरती गई है। इसलिए इस पूरे नुकसान और मानसिक परेशानी के लिए ई-कॉमर्स कंपनी और विक्रेता दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

नो-कॉस्ट ईएमआई पर मंगाया था फोन, चार्जर और कवर पहुंचे सही : यह मामला मुंबई के पवई इलाके के रहने वाले एक ग्राहक से जुड़ा है। उन्होंने 22 अप्रैल 2023 को फ्लिपकार्ट से 1,11,793 रुपये की कीमत वाला एपल आईफोन 14 प्रो (128 जीबी) नो-कॉस्ट ईएमआई योजना के तहत खरीदा था। फोन के साथ ग्राहक ने अलग से चार्जर और मोबाइल कवर का भी आर्डर दिया था, जो बिल्कुल सही हालत में डिलीवर हुआ। लेकिन अगले दिन जब मुख्य पार्सल आया, तो उसमें आईफोन की जगह दाढ़ी का तेल निकला। ग्राहक ने अप्रैल से मई 2023 के बीच कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से लगातार संपर्क किया और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज भी सौंपे, फिर भी उन्हें न तो नया फोन मिला और न ही पैसे वापस किए गए।

45 दिन के भीतर ब्याज सहित 1.81 लाख चुकाने का अल्टीमेटम : उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट और सेलर को कड़ा निर्देश दिया है कि वे 45 दिनों के भीतर ग्राहक को 1,11,793 रुपये की पूरी राशि लौटाएं। इस रकम पर 22 अप्रैल 2023 से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा, ग्राहक को हुए भारी मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 20,000 रुपये अलग से देने का आदेश सुनाया गया है। वहीं, इस मामले में एपल इंडिया को राहत देते हुए कोर्ट ने उसके खिलाफ शिकायत खारिज कर दी है। आयोग ने माना कि एपल केवल स्वतंत्र विक्रेताओं के जरिए अपने उत्पाद बेचता है और पार्सल में गलत सामान निकलने या सेवा में कमी के लिए निर्माता कंपनी की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशन

नई दिल्लीः राजधानी के जंतर-मंतर पर जारी सियासी घमासान ने आम जनता की रफ्तार पर लगातार तीसरे दिन भी सख्त पहरा लगा दिया है। अगर आप आज दफ्तर या कॉलेज जाने के लिए घर से निकल रहे हैं और आपका रूट लुटियंस या मध्य दिल्ली से होकर गुजरता है, तो यह खबर आपके लिए किसी जरूरी अलर्ट से कम नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के कड़े निदेर्शों के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने शुक्रवार सुबह साढ़े सात बजे से 17 प्रमुख स्टेशनों के दरवाजे यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए हैं, जिससे सड़कों से लेकर मेट्रो की भूमिगत दुनिया तक में भारी असमंजस और असुविधा का माहौल बन गया है।

इन तीन स्टेशनों पर मिलेगी लाइन बदलने की छूट, बाहर निकलने पर पाबंदीः डीएमआरसी के अनुसार, सुरक्षा कारणों से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक सभी 17 प्रभावित स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट पूरी तरह से सील रहेंगे। हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो लाइन बदलने (इंटरचेंज सुविधा) की अनुमति दी गई है। इसका मतलब है कि यात्री एक लाइन से दूसरी लाइन की ट्रेन तो पकड़ सकेंगे, लेकिन उन्हें स्टेशन परिसर से बाहर सड़क पर कदम रखने की इजाजत नहीं होगी।

केंद्रीय दिल्ली के 17 स्टेशनों के गेट पर लटका तालाः डीएमआरसी द्वारा जारी आदेश के तहत जिन 17 प्रमुख स्टेशनों पर आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और बाराखंभा रोड शामिल हैं। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत के पास स्थित सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ और दिल्ली गेट स्टेशन के गेट भी यात्रियों के लिए नहीं खोले जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों पर भी अगले आदेश तक ताला लटकता रहेगा, इसलिए इन इलाकों में जाने वाले लोग वैकल्पिक रास्तों का ही चुनाव करें।

लगातार तीसरे दिन यात्री बेहाल, सड़कों पर भी रेंग रहा है ट्रैफिक : मेट्रो के पहियों पर लगी इस अचानक ब्रेक से कामकाजी लोगों और छात्रों की आफत कई गुना बढ़ गई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली के दिल में सफर करने वालों को इस मानसिक और शारीरिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इससे पहले बुधवार और बृहस्पतिवार को भी ये सभी 17 स्टेशन करीब 14 घंटे तक बंद रहे थे। हालांकि, बृहस्पतिवार शाम को भारी दबाव के बाद राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय के प्रवेश द्वार खोले जा सके थे, जबकि बाकी स्टेशन दिनभर बंद रहे। मेट्रो गेट बंद होने से सड़कों पर बसों, कैब और निजी वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया है, जिससे कई प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक रेंगने लगा है।

स्कूल में मिड डे मील खाने से 94 बच्चे बीमार, मचा हड़कंप

सुपौलः बिहार के सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र स्थित मिरजबा राजकीय मध्य विद्यालय में बुधवार को मिड डे मील खाने के बाद 94 बच्चे बीमार हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विद्यालय में मिड डे मील ग्रहण करने के कुछ देर बाद बच्चों को चक्कर आने, घबराहट और बेचैनी की शिकायत होने लगी। इसके बाद विद्यालय प्रशासन ने सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया।

घटना की सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज के अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विभाष कुमार तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बच्चों के उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। चिकित्सकों ने सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद उनकी स्थिति सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

अमेरिका पर होगा 9/11 जैसा हमला, होर्मुज को लेकर ट्रंप की चेतावनी पर ईरान की बड़ी धमकी

एजेंसी/ तेहरान/ वाशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच धमकियों का दौर रुक नहीं रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद किए जाने से आगबबूला हो गए हैं, वहीं अमेरिका के लगातार हमलों के बाद ईरान भी बौखला गया है। इस बीच अब ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने अगर जल्द ही अपने हमले नहीं रोके, तो उस पर 9/11 जैसा होगा। इस धमकी के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तबाही की आशंका गहरा गई है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की चेतावनी दी थी। इसके बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने डरावनी धमकी दे डाली। आईआरजीसी ने अमेरिका को 9/11 जैसे हमले की धमकी देते हुए कहा कि अगर यह युद्ध जारी रहा, तो अमेरिका में राष्ट्रीय शोक की स्थिति पैद कर जाएगी।

ईरान का मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमलाः 2026 के ईरान युद्ध में एक नया और खतरनाक मोड़ आया है। ईरान ने गुरुवार को जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल जवाबी हमले किए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरीगार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थाड़ (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी एमक्यू-9 रीपर ड्रोन के ऑपरेशन बेस पर भी हमला किया गया। इससे पहले अमेरिका ने बुधवार को लगातार 12वीं रात ईरान में इराक बॉर्डर पर स्थित शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमला किया।

अमेरिकी सीएआई फैसिलिटी पर ड्रोन अटैकः ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सीआईए की सीक्रेट फैसिलिटी पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों की सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए अमरीकी खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या रूस ने ईरान को टारगेटिंग जानकारी या एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है। चार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन हमलों की सटीकता और रूस-ईरान के लंबे तकनीकी सहयोग को संदिग्ध माना जा रहा है। यह घटना सामान्य नहीं है, क्योंकि सीआईए की विदेशी सुविधाएं बेहद सीक्रेट होती हैं।

हाउतियों ने लाल सागर में सऊदी के दो तेल टैंकरों पर हमला किया

रियादः यमन के हाउती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने गुरुवार को लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला किया। इस हमले के साथ ही हाउती संगठन ने संकेत दिए हैं कि वह सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी कर सकता है। इससे लाल सागर के इस महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग में तनाव और बढ़ गया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाए जाने की पुष्टि की है। अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अंसार अल्लाह के नाम से जाने जाने वाले हूती समूह ने ले ली है। हाउती समूह ने सऊदी अरब पर अपने नियंत्रण वाले यमनी इलाकों की घेराबंदी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सऊदी पाबंदियों के जवाब में ही वे यह समुद्री कार्रवाई कर रहे हैं। हाउती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि उनका संगठन सऊदी अरब के

खिलाफ अपने नौसैनिक अभियानों को जारी रखेगा और घेराबंदी के बदले घेराबंदी की नीति पर कायम रहेगा।

ट्रंप बोले, हाउतियों ने फिर हमला किया, तो दोनों को सजा मिलेगी : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर यमन के हाउती विद्रोहियों ने जहाजों पर फिर हमला किया तो अमरीका, ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। टंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाउती विद्रोहियों ने फिर से जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बुधवार रात सऊदी अरब के दो जहाजों पर हमला किया। अगर वे दोबारा ऐसा करते हैं तो अमरीका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि वह ईरान के इशारे पर काम करने वाला संगठन है। अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो ईरान और हाउती, दोनों को कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

फ्रांस की अपील, सऊदी तेल टैंकरों पर हमले रोकें हाउतीः फ्रांस ने गुरुवार को ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों से सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमले तुरंत बंद करने की अपील की। फ्रांस ने इन हमलों को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हाउतियों की ओर से सऊदी तेल टैंकरों पर किए जा रहे हमले गैर-जिम्मेदाराना हैं और यह हालात को गंभीर रूप से बिगाड़ने वाला कदम है।

न्यूज IN ब्रीफ

कार्यपालक अभियंता अनूप कुमार हसदा विभाग को दे रहे हैं भरपूर विकास गति

चक्रधरपुर पेय जल स्वच्छता विभाग के नव पदस्थापित कार्यपालक अभियंता अनूप कुमार हसदा के द्वारा 11 वे कार्यपालक अभियंता के रूप में 6जुलाई को अपना पदभार ग्रहण किया है पदभार ग्रहण करने के पश्चात मेंइन दोनों विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से किया जा रहा है श्री हांसदा का कहना है कि विभाग अधीन कार्यों को संवेदक के द्वारा समय पर पूर्ण करने की दिशा में उन्हें निर्देश दे दिया गया है तथा समय अवधि के अंतर्गत अपने कार्य को पूर्ण करें जिससे कि निर्धारित अवधि में योजना पूर्ण हो सके कार्यपालक अभियंता के द्वारा नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है नये कार्यपालक अभियंता इससे पूर्व चक्रधरपुर में सहायक अभियंता के रूप में पद स्थापित रह चुके हैं जिसके फल स्वरुप इस क्षेत्र के भौगोलिक और समस्याओं तथा कार्यों को भली भांति जानते भी हैं जिसका लाभ विभाग को मिल रहा है।

बंदगांव की पहाड़ियां भरी है प्राकृतिक खूबसूरती से

संवाददाता : झारखंड के चक्रधरपुर रांची मुख्य मार्ग पर स्थित बंदगांव की पहाड़िया एवं जंगल खनिज संपदा से भरी हुई है इन दोनों बरसात के मौसम में में रोड के समीप ही जंगलों में कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिलता है इन पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार की मशरूम पाई जाती है जो कि बड़े-बड़े शहरों में काफी महंगे दामों में बिकती है।

हजारीबाग में कांग्रेस का धरना तो जेएमएम ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका

हजारीबाग : नीट पेपर लीक, दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता और राहुल गांधी को हिरासत में लेने की घटना को लेकर झारखंड में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हजारीबाग में कांग्रेस ने समाहरणालय के सामने धरना देकर विरोध दर्ज कराया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है।

झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हजारीबाग में अलग-अलग विरोध-प्रदर्शन किया है। हजारीबाग समाहरणालय परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से ₹लोकतंत्र बचाओ-छात्र न्याय आंदोलन₹ के तहत एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में झारखंड के पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के कार्यकताओं के साथ शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों, नेताओं एवं छात्र-युवा संगठनों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। धरना के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखने की मांग उठाई गई।

झामुमो ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका

वहीं दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग जिला कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झामुमो नेताओं ने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग लोकतंत्र के खिलाफ है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

पार्टी ने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रही है और लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। दिल्ली में हुई घटना ने पूरे देश के राजनीति को गर्म कर दिया है। विभिन्न राज्यों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल, आने वाला समय में क्या कार्रवाई होगी यह देखना भी दिलचस्प होगा।

उपायुक्त से विधि व्यवस्था ड्यूटी में गृह रक्षक बढ़ाने की मांग

जमशेदपुर : गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ प्रदेश समिति के तत्वाधान में दिनेश प्रसाद यादव प्रदेश संगठन सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से भेंट कर विधि व्यवस्था संधारण नियुक्त होने वाले गृह रक्षको की संख्या बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया संयुक्त बिहार के समय से ही विधि व्यवस्था ड्यूटी में जिला पुलिस के साथ 250 गृह रक्षको स्वीकृती प्रदान की गई थी। वर्तमान समय में 238 गृहरक्षक जवान विधि व्यवस्था ड्यूटी में हैं तथा थानाा चालक, एसएसपी, उपायुक्त तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं अन्य स्थानों पर विधि व्यवस्था ड्यूटी में कार्यरत है। उपायुक्त से मांग किया गया कि, जमशेदपुर पुलिस जिला में गृह रक्षों की संख्या बढ़ाने की पहल करे। उपायुक्त से रामेश्वरी कालिंदी, आजाद अंसारी, सतोष कुमार यादव एवं अन्य गृह रक्षक शामिल हुए।

एमजीएम में डिजिटल माइक्रोस्कोप से पढ़ाई की तैयारी

जमशेदपुर : एमजीएम मेडिकल कॉलेज में परंपरागत माइक्रोस्कोप की जगह डिजिटल माइक्रोस्कोप से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए निर्माण कंपनी ने कॉलेज में उपकरण का डेमो भी दिया है। पैथोलॉजी विभाग में फिलहाल पारंपरिक माइक्रोस्कोप से पढ़ाई कराई जाती है। इसमें एक स्लाइड को एक समय में केवल एक छात्र ही देख सकता है। सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उन्हें बारी-बारी से माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है।

सिमडेगा में विकास योजनाओं की समीक्षा

आयुष्मान कार्ड निर्माण और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर डीडीसी का जोर

कम खर्च वाले प्रखंडों को एक सप्ताह में व्यय बढ़ाने का निर्देश

विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के आदेश

संवाददाता

सिमडेगा : उप-विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, श्इ-ऋफ्अट-ऋ् प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना, पीएम-जनमन एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारतझ्रमुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर विशेष जोर दिया गया। उप-विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी राशन कार्डधारी सूचीबद्ध अस्पतालों में 15 लाख रुपये तक का निःशुल्क कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से ई-केवाईसी कराकर आयुष्मान कार्ड बनवाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार के पात्र हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को विशेष शिविर

लगाकर पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में वीवी जी रामजी के तहत कार्य मांग के अनुरूप एमआर जनरेशन, मानव दिवस सृजन, युक्तधारा पोर्टल पर प्रविष्टि, जियो टैगिंग और मजदूरों के ई-केवाईसी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और पीएम-जनमन के लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर बल दिया गया।

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान 40 प्रतिशत से कम व्यय वाले प्रखंडों को एक सप्ताह के भीतर योजनाओं का चयन कर राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बीआरजीएफ, 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की राशि, पेसा नियमावली-2025 के अनुपालन, ग्राम सभा कार्यालय भवन, सहायक सचिव चयन, ग्राम सभा के बैंक खाते तथा ईईएसएल के लंबित भुगतानों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में परियोजना पदाधिकारी मनरेगा अमरेन्द्र कुमार, डीपीएम पंचायती राज शेफर्ड तिर्की, प्रखंड समन्वयक पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देवी धाम में अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय, खुले में शौच को मजबूर श्रद्धालु

मंदिर समिति ने उपायुक्त से लगाई गुहार, मेले में लाखों श्रद्धालुओं को होती है भारी परेशानी

मेट्रोरेज संवाददाता

हैदरनगर : झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित प्रसिद्ध हैदरनगर देवी धाम के निकट वर्षों से अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय श्रद्धालुओं के लिए बड़ी समस्या बन गया है। निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण विशेषकर मेले के दौरान हजारों-लाखों श्रद्धालुओं, खासकर महिलाओं को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे मंदिर परिसर की स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा दोनों प्रभावित हो रही हैं। मंदिर प्रबंध समिति के सचिव रामाश्रय सिंह एवं अन्य सदस्यों ने इस गंभीर समस्या को लेकर पलामू के उपायुक्त को पत्र सौंपकर अधूरे सामुदायिक शौचालय का निर्माण शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। समिति का कहना है कि सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त बनाना है, लेकिन देवी धाम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर यह उद्देश्य अधूरा दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार, 14वें वित्त आयोग की राशि से पंचायत समिति मद के तहत तत्कालीन प्रमुख के पति लाल बाबू द्वारा देवी धाम के निकट सरकारी भूमि पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण शुरू कराया गया था। निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद अचानक बंद हो गया और आज तक पूरा नहीं हो सका।समिति के अनुसार, हैदरनगर देवी धाम में अश्विन और चैत्र माह में लगने वाला प्रसिद्ध 'भूत मेला' पूरे क्षेत्र की धार्मिक आस्था का केंद्र है। हर वर्ष दो बार आयोजित इस मेले में झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। महिलाओं की संख्या अधिक होने के बावजूद मंदिर परिसर में उपलब्ध एकमात्र शौचालय भीड़ के सामने नाकाफी साबित होता है। समिति ने बताया कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर के कार्यकाल में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शौचालय निर्माण शुरू कराया गया था, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद निर्माण कार्य ठप पड़ गया। नतीजतन, मेले के दौरान श्रद्धालुओं को खुले में शौच करना पड़ता है, जिससे मंदिर के आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

राणा राम बदन सिंह सामाजिक समरसता के प्रतीक थे : हृदयानंद मिश्र

मेट्रोरेज संवाददाता

मेदिनीनगर : झारखंड प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्य एवं अधिवक्ता हृदयानंद मिश्र ने वरिष्ठ समाजसेवी एवं सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी राणा राम बदन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना केवल एक परिवार की क्षति नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।

श्री मिश्र ने कहा कि राणा राम बदन सिंह मेरे पड़ोसी ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य से बढ़कर थे। विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक एवं समसामयिक विषयों पर उनसे निरंतर सार्थक चर्चा होती रहती थी। उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव, सरल स्वभाव, निष्पक्ष सोच और समाज के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणास्त्रोत रहेगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के पद पर अपनी सेवाएँ देने वाले राणा राम बदन सिंह एक अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके आवास पर प्रत्येक माह श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण कथा का आयोजन होता था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सहभागी बनते थे। वे आध्यात्मिकता, सामाजिक समरसता और प्रगतिशील विचारों के सशक्त समर्थक थे तथा सभी वर्गों के लोगों को समान सम्मान और स्नेह देने में विश्वास रखते थे।

श्री मिश्र ने बताया कि 85 वर्ष की आयु में आज सायं लगभग 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस

ली। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके परिवार में तीन पुत्र-पुत्रियाँ, बहुएँ, दामाद, नाती-पोते एवं अन्य परिजन हैं। उनके सुपुत्र राणा अरुण सिंह राष्ट्रीय नवीन मेल समाचार पत्र के संपादक हैं।

हृदयानंद मिश्र ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि राणा राम बदन सिंह के आदर्श, सामाजिक समरसता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा उनकी सादगी सदैव स्मरणीय रहेगी।

फिल्म निर्माता एवं निर्देशक डॉ वीरेंद्र कुमार सम्मानित

संवाददाता

कोडरमा : कोलकाता में आयोजित 15वें शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोडरमा के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं फिल्म निमार्ता एवं निर्देशक डॉ. वीरेंद्र कुमार और विपिन जाते को दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

इस शार्ट फिल्म को मिला ज्यूरी मेंशन अवार्ड

कोलकाता में आयोजित इस फिल्म महोत्सव में राजवीर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस की शार्ट फिल्म 'लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री' को ज्यूरी मेंशन अवार्ड जबकि म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार हो गया' को बेस्ट म्यूजिक वीडियो ज्यूरी अवार्ड प्रदान किया गया है.

मिल रहे सम्मान से और बढ़ी जिम्मेदारीः फिल्म निमार्ता डॉ. वीरेंद्र कुमार

पुरस्कार मिलने पर डॉ. वीरेंद्र कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि लगातार मिल रहे सम्मान से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि उनकी टीम सामाजिक सरोकारों और जन जागरूकता से जुड़े विषयों पर शॉर्ट फिल्म और म्यूजिक वीडियो का निर्माण करती

रही है. उन्होंने कहा कि 'लूटन सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री' वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर आधारित व्यंग्यात्मक फिल्म है, जो महज 15 मिनट में जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश देती है.

हमारी फिल्मों में सामाजिक जरूरतों पर विशेष ध्यान : वहीं म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार हो गया' के माध्यम से पढ़ाई और नौकरी के दौरान बनने वाले रिश्तों की वास्तविकता को दशार्ने का प्रयास किया गया है. वहीं सह निमार्ता विपिन जाते ने बताया कि उनकी फिल्मों में सामाजिक जरूरतों और दर्शकों की पसंद के साथ तकनीकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. शायद यही कारण है कि उनकी प्रस्तुतियों को विभिन्न मंचों पर लगातार सम्मान मिल रहा है.

इंकैबकर्मियों को कोर्ट के फैसले पर मिलेगा पीएफ

संवाददाता

जमशेदपुर : इंकैब इंडस्ट्रीज के पुनरुद्धार के लिए वेदांता समूह एनसीएलटी के आदेश के तहत काम शुरू कर दिया है। इस आदेश के तहत रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने कर्मचारियों को उनके दावों का भुगतान भी करने लगा है। अब कर्मचारियों को पीएफ (भविष्य निधि) को लेकर आशंका है। पीएफ के दावों को लेकर पीएफ विभाग ने एनसीएलएटी दिल्ली में अपील दायर किया है। हालांकि एनसीएलटी कोलकाता ने पीएफ मद में 164 करोड़ के दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस राशि का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। एनसीएलटी के फैसले को पीएफ विभाग जमशेदपुर की ओर से एनसीएलएटी नई दिल्ली में अपील दायर किया गया है।

एनसीएलएटी में अंकेक्षित बैलेंस शीट जमा किया गया है। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2011 तक का कंपनी के पास अंकेक्षित बैलेस शीट तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, वेदांता समूह ने पीएफ मामले में एनसीएलएटी के फैसले का इंतजार कर रही है। कंपनी एनसीएलएटी के फैसले को मानेगी। एनसीएलएटी के फैसले में पीएफ की जो राशि तय की जाएगी। उस राशि का भुगतान वेदांता समूह करने को तैयार है।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए गए दिशा- निर्देश

गांधी मैदान, गोड्डा में होगा ध्वजारोहण/मुख्य कार्यक्रम

संवाददाता

स्कूली छात्र /छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी का होगा आयोजन। विनय मिश्रा, समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री लोकेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम, मुख्य समारोह स्थल पर मंच का निर्माण, मुख्य समारोह स्थल के मंच पर बैठने की व्यवस्था, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण , मुख्य समारोह स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था, आमंत्रण कार्ड का प्रकाशन एवं वितरण, प्रभात फेरी ,परेड का आयोजन, राष्ट्रगान का पूर्वाभ्यास, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद जवान के आश्रितों को सम्मानित, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित, मुख्य समारोह स्थल पर अग्निशमन की व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल पर विधि-व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल पर पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था/ विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को इसकी तैयारी करने को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए।

10 अगस्त से होगा परेड का पूर्वाभ्यास-बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 10 अगस्त पूर्वाह्न 07:00 बजे से परेड का पूर्वाभ्यास मुख्य समारोह स्थल पर आरंभ किए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम के सफल

संचालन को लेकर सर्जेंट मेजर से विचार-विमर्श की गई ।

उक्त बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएं तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन भव्य, गरिमामय, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके।

बैठक के दौरान आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा विधि व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त को लेकर परेड का पूर्वाभ्यास मुख्य समारोह स्थल पर होगा। उनके द्वारा विधि व्यवस्था संधारण समेत कई बिंदओं पर भी चर्चा की गई एवं जरूरी दिशा -निर्देश दिए गए।

बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कमिटी के सदस्यों के द्वारा अपनी राय प्रकट की गई,एवं उनके द्वारा दिए गए सुझाव को उपायुक्त के द्वारा सुनकर त्रुटियों मे सुधार लाने के निर्देश दिए गए।